घटती घटना

सत्य के साथ...जनहित में बात...

www.ghatatighatana.com अम्बिकापुर,वर्ष 22, अंक - 222- शनिवार 13- जून 2026,पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रूपये RNI Reg.No.- CHHHIN/2004/15050,डाक पंजीयन. क्रं. 13/Surguja DN/ 2026-2028

डीजल-पेट्रोल की खुली बिक्री पर लगी रोक : सरकार ने कमर्शियल और इंडस्ट्रियल यूजर्स के लिए तय की 200 लीटर की सीमा...

नई दिल्ली,12 जून 2026। देश के कुछ हिस्सों में पेट्रोल और डीजल की मांग में अचानक आई असामान्य तेजी को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने एक आधिकारिक आदेश जारी कर सभी इंडस्ट्रियल,कमर्शियल और इंस्टीट्यूशनल (औद्योगिक, वाणिज्यिक और संस्थागत) यूजर्स पर पेट्रोल पंपों से ईंधन खरीदने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।

अब इन सभी बड़े उपभोक्ताओं को अपनी जरूरत का तेल सिर्फ 'बल्क सेल पॉइंट्स' से ही खरीदना होगा। दरअसल, वेस्ट एशिया (मध्य पूर्व) संकट के चलते अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की लागत काफी बढ़ गई है। इसके बावजूद आम जनता को महंगाई से राहत देने के लिए देश में पेट्रोल-डीजल की खुदरा कीमतें नहीं बढ़ाई गईं। इसका नतीजा यह हुआ कि दिल्ली जैसे शहरों में रिटेल डीजल (95.20 रुपये प्रति लीटर) और थोक यानी बल्क डीजल (134.50 रुपये प्रति लीटर) के बीच 39 रुपये से अधिक का भारी अंतर आ गया। बल्क पॉइंट से तेल महंगा मिलने के कारण टेलीकॉम टावर,फैक्ट्रियां और बड़ी इंडस्ट्रीज जैसे थोक खरीदार नुकसान से बचने के लिए आम जनता के खुदरा पेट्रोल पंपों से भारी मात्रा में खरीदारी करने लगे थे,जिससे वहां किल्लत की स्थिति बनने लगी थी।

प्रति वाहन अधिकतम 200 लीटर की सीमा तय...

सरकार द्वारा जारी नए नियमों के तहत अब खुदरा पेट्रोल पंपों पर डीजल की बिक्री को केवल वाहनों के मुख्य ईंधन टैंक या फिर पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन द्वारा स्वीकृत कंटेनरों तक ही सीमित कर दिया गया है। इसके साथ ही किसी भी प्रति ग्राहक या वाहन के लिए प्रतिदिन अधिकतम 200 लीटर डीजल खरीदने की सीमा (कैपिंग) तय कर दी गई है। सरकारी आदेश में यह भी साफ किया गया है कि खुदरा पंपों से खरीदे गए इस डीजल को आगे किसी भी स्थिति में दोबारा बेचा नहीं जा सकेगा। देश के कुछ हिस्सों में पेट्रोल और डीजल की मांग में अचानक आई असामान्य तेजी को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने एक आधिकारिक आदेश जारी कर सभी इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और इंस्टीट्यूशनल (औद्योगिक, वाणिज्यिक और संस्थागत) यूजर्स पर पेट्रोल पंपों से ईंधन खरीदने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। अब इन सभी बड़े उपभोक्ताओं को अपनी जरूरत का तेल सिर्फ 'बल्क सेल पॉइंट्स' से ही खरीदना होगा।

90 दिनों तक प्रभावी रहेगा नया नियम

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने इस जमाखोरी और असामान्य बिक्री को रोकने के लिए 11 जून को 'मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीजल (खुदरा दुकानों के माध्यम से आपूर्ति का अस्थायी विनियमन) आदेश, 2026' जारी किया है। इस अधिसूचना के तहत ईंधन खुदरा विक्रेताओं और तेल विपणन कंपनियों को अगले 90 दिनों तक खुदरा दुकानों से इस तरह की थोक खरीद पर पूरी तरह अंकुश लगाने का निर्देश दिया गया है।

संक्षिप्त समाचार

इंदौर में सड़क हादसे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के भतीजे की मौत

भोपाल,12 जून 2026। इंदौर में एक दर्दनाक सड़क हादसे में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के भतीजे प्रशांत सिंह (29) की मौत हो गई। घटना शिप्रा थाना क्षेत्र में रात करीब 11 बजे हुई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी सक्रिय हो गए। शुक्रवार सुबह प्रशांत सिंह के पार्थिव शरीर को विशेष विमान से दिल्ली भेजा गया,जबकि उनका अंतिम संस्कार उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में किया जाएगा। पुलिस के अनुसार, प्रशांत सिंह अपने तीन साथियों के साथ किसी निजी कार्य से देवास आए थे। काम पूरा करने के बाद वे कार से इंदौर लौट रहे थे। रास्ते में शिप्रा क्षेत्र के पास उन्होंने वाहन रोका। इसी दौरान जब प्रशांत कार में वापस बैठने जा रहे थे, तभी तेज रफ्तार और अनियंत्रित बस ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में उनके सिर पर गंभीर चोटें आईं। साथी उन्हें तत्काल अरबिंदो अस्पताल लेकर पहुंचे,जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही भाजपा नेता,प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस अस्पताल पहुंच गए। देर रात पोस्टमॉर्टम की प्रक्रिया पूरी कर ली गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार बस चालक और वाहन की तलाश शुरू कर दी है।

दिल्ली के तुगलकाबाद में बिल्डिंग में आग,3 मौतें

6 झुलसे,पार्किंग में टू-व्हीलर में आग लगी

नई दिल्ली,12 जून 2026। दिल्ली के तुगलकाबाद इलाके में एक बिल्डिंग में आग लगने से तीन लोगों की मौत हो गई। इनमें एक युवक और दो महिलाएं हैं। 6 लोगों को बचाया गया है, सभी अस्पताल में भर्ती हैं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, आग पार्किंग में खड़ी गाड़ियों में लगी थी। धीरे-धीरे आग पांच मंजिला बिल्डिंग में फैल गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने छत का ताला काटकर लोगों को बचाया। फायर डिपार्टमेंट के अनुसार, गुरुवार देर रात 2:35 बजे से 2:37 बजे के बीच इमरजेंसी कॉल मिलीं। आग तारा अपार्टमेंट के पास गली नंबर 1 में स्थित एक इमारत में लगी थी। इमारत के अंदर कई लोगों के फंसे होने की खबर मिलने के बाद फायर फाइटर्स ने रेस्क्यू शुरू किया। 3:45 बजे तक आग पर काबू पा लिया गया। एक चश्मदीद ने बताया कि, हम लोग पड़ोस में रहते हैं। आग लगने की खबर मिलते ही वहां पहुंचे तो देखा कि ग्राउंड फ्लोर पर खड़ी गाड़ियों में एक-एक करके ब्लास्ट हो रहा था। हमने पानी का इस्तेमाल करके आग बुझाई। हमने पीछे की तरफ से भी लोगों को बचाया। उन्हें नीचे उतारने के लिए साड़ियों का इस्तेमाल किया और लड़कियों को बाहर निकालने के लिए पीछे की सुरक्षा ग्रिल काटी। बिलडिंग में कुल 9 परिवार रहते हैं कुछ बाहर गए थे। घटना के वक्त करीब 20-22 लोग इमारत में रहे होंगे। फायर विभाग के एडीओ यशवंत मीणा ने बताया कि पार्किंग में खड़ी तीन स्कूटी, दो बाइक और एक साइकिल जल गई। आग और धुआं ग्राउंड फ्लोर से पांचवीं मंजिल तक फैल गया, जिससे निचली मंजिलों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। संकरी गली में बनी पांच मंजिला इमारत होने के कारण राहत कार्य में दिक्कतें आईं। छत का गेट बंद होने पर उसका ताला तोड़कर अंदर पहुंचे और वहां फंसी दो लड़कियों को सुरक्षित बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया।

दीदी की पार्टी में बगावत...

लोकसभा अध्यक्ष के पास पहुंचे टीएमसी के 19 बागी सांसद

नई दिल्ली,12 जून 2026। पश्चिम बंगाल की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के भीतर एक ऐसा सियासी तूफान उठा है,जिसने दिल्ली से लेकर कोलकाता तक सबको चौंका दिया है। पार्टी के 20 में से 19 बागी सांसदों ने टीएमसी से अलग होने का पूरा मन बना लिया है। इन सभी सांसदों ने 18 मई को आधिकारिक तौर पर अपने नामों की लिस्ट लोकसभा अध्यक्ष (स्पीकर) के दफ्तर को सौंप दी है। बंगाल की सियासत में इसे अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। इस बगावत ने टीएमसी आलाकमान की नींद उड़ा दी है। सूत्रों के मुताबिक,बागी सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र सौंपकर संसद में अपने एक अलग गुट को मान्यता देने की मांग की है। राजनीति के जानकारों का कहना है कि यह पूरी प्लानिंग बेहद सोच-समझकर की गई है। दरअसल, दल-बदल कानून की कार्रवाई से बचने के लिए किसी भी बागी खेमे को दो-तिहाई सांसदों का समर्थन जरूरी होता है।

दिग्गज निशानेबाज जसपाल राणा का निधन

49 साल की उम्र में ली आखिरी सांस,खेल जगत में शोक की लहर,पीएम मोदी ने जताया शोक

नई दिल्ली,12 जून 2026। भारतीय खेल इतिहास के सबसे चमकदार और दिग्गज निशानेबाजों में शामिल जसपाल राणा का निधन हो गया है। वह महज 49 वर्ष के थे। बताया जा रहा है कि जर्मनी से लौटने के बाद अचानक उनकी तबीयत काफी बिगड़ गई थी,जिसके बाद उन्हें दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था,जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके इस तरह अचानक चले जाने से पूरे भारतीय खेल जगत और उनके चाहने वालों में शोक की लहर दौड़ गई है।

पीएम मोदी ने जताया दुःख : जसपाल राणा के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुःख व्यक्त किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि जसपाल राणा का जाना भारतीय खेल जगत के लिए एक ऐसी अपूरणीय क्षति है जिसे कभी पूरा नहीं किया जा सकता। उन्होंने खेल के मैदान पर भारत का गौरव बढ़ाने के साथ-साथ नई पीढ़ी को तैयार करने में भी अभूतपूर्व योगदान दिया।

गढ़वाल से ग्लोबल मंच तक का सफर : 28 जून 1976 को उत्तराखंड के एक गढ़वाली परिवार में जन्मे जसपाल राणा

को निशानेबाजी विरासत में मिली थी। उनके पिता नारायण सिंह राणा सेना के पूर्व अधिकारी थे और बाद में उत्तराखंड के पहले खेल मंत्री भी बने। पिता की देखरेख में ही उन्होंने बचपन से शूटिंग के गुर सीखे और महज 12 साल की उम्र में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी धाक जमा दी। उन्होंने 1988 में अहमदाबाद नेशनल शूटिंग चैम्पियनशिप में सिल्वर जीतकर सबका ध्यान खींचा, जिसके बाद 1994 में इटली के मिलान में हुई जूनियर वर्ल्ड शूटिंग चैम्पियनशिप में वर्ल्ड रिकॉर्ड स्कोर बनाकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सनसनी फैला दी। उन्होंने 1996 के अटलांटा ओलंपिक में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया था।

राज्यसभा नामांकन रद्द होने के खिलाफ मीनाक्षी की याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बोलीं...पहले वोट चोरी होती थी,इस बार सीट चोरी हुई

नई दिल्ली,12 जून 2026। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका खारिज कर दी। उन्होंने राज्यसभा चुनाव के लिए उनका नामांकन रद्द किए जाने के फैसले को चुनौती दी थी। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में सीधे रिट याचिका नहीं सुनी जा सकती। अगर उन्हें फैसले पर आपत्ति है तो वे चुनाव याचिका दायर करें। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस एएस चंदूरकर की बेंच ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 329 चुनाव प्रक्रिया में अदालतों के हस्तक्षेप को सीमित करता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस मामले में रिट पिटीशन पर सुनवाई नहीं कर सकता। नामांकन रद्द करने का फैसला सही था या गलत,अदालत ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। कोर्ट ने कहा...चुनाव से जुड़े ऐसे विवादों का समाधान चुनाव याचिका के जरिए किया जाना चाहिए। मीनाक्षी नटराजन चाहें तो चुनाव याचिका दाखिल कर इस फैसले को चुनौती दे सकती हैं। दरअसल,मध्य प्रदेश की तीसरी सीट के लिए कांग्रेस ने मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार बनाया था। कांग्रेस के पास पर्याप्त

संख्या बल भी था,लेकिन 9 जून को मीनाक्षी का नामांकन फॉर्म निरस्त कर दिया गया। इसके खिलाफ कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। याचिका खारिज होने पर मीनाक्षी ने कहा कि पहले वोट चोरी होती थी,इस बार सीट चोरी हुई।

मीनाक्षी ने कहा था-चुनाव लड़ने दिया जाए : सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मीनाक्षी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था, 'रिटर्निंग ऑफिसर ने उन्हें शुरुआती चरण में ही बाहर कर दिया। उन्हें चुनाव लड़ने दिया जाए, अगर उन्हें वोट नहीं मिलते हैं तो वे हार जाएंगी, यही लोकतंत्र की प्रक्रिया है।' मध्य प्रदेश की तीसरी राज्यसभा सीट के लिए कांग्रेस के पास पर्याप्त संख्या बल था,लेकिन 9 जून को भाजपा ने आपत्ति लगाई कि कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन ने अपने खिलाफ दर्ज एक केस की जानकारी नामांकन पत्र में नहीं दी। इसे स्वीकार करते हुए रिटर्निंग अधिकारी अरविंद शर्मा ने मीनाक्षी का नामांकन निरस्त कर दिया था। इसके बाद 11 जून को मध्य प्रदेश की तीनों सीटों पर भाजपा के राज्यसभा उम्मीदवारों रजनीश अग्रवाल, तरुण चुघ और महेश केवट को निर्विरोध चुने जाने के सर्टिफिकेट दे दिए गए।

सिंघार ने कहा...चुनाव आयोग ने लोकतंत्र का गला घोंटा : शुक्रवार को कांग्रेस ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इसमें मीनाक्षी नटराजन ने कहा...मेरे खिलाफ मात्र एक लीगल नोटिस है। उसकी पूरी जानकारी मैंने मेरे ईसीआई मेमोरेंडम में दी है। जिस पर आज तक अदालत ने संज्ञान नहीं लिया। फार्म 26 में ऐसा कोई कॉलम नहीं है, जिसमें लिखा जाए कि प्राइवेट कम्प्लेंट के बारे में सूचना दीजिए। अगर कोई ऐसा कॉलम होता तो हम यह सूचना जरूर देते।

चुनावी भाषण को लेकर कोलकाता के हेयर स्ट्रीट थाने में ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर

कोलकाता,12 जून 2026। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए एक विवादित बयान को लेकर राजधानी कोलकाता के हेयर स्ट्रीट थाने में प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज की गई है। पुलिस ने लिखित शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान ममता बनर्जी ने एक विशेष समुदाय को लेकर टिप्पणी की थी। अपने भाषण में उन्होंने कहा था कि यदि एक समुदाय एकजुट हो जाए तो वह विरोधियों की बारह बजा सकता है। साथ ही उन्होंने लोगों से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के खिलाफ भी भड़काया था। इस बयान को लेकर उस समय भी राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया था। इसके पूर्व इस संबंध

में नेताजी सुभाषचंद्र बोस रोड निवासी तुषारकांति दास ने 20 मई को नेताजीनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में उन्होंने ममता बनर्जी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की थी। उनका आरोप था कि भले ही किसी समुदाय का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया गया हो, लेकिन इस प्रकार की टिप्पणी सांप्रदायिक सौहार्द को प्रभावित कर सकती है और विभिन्न समुदायों के बीच तनाव पैदा कर सकती है। शिकायतकर्ता ने यह भी दावा किया है कि कोलकाता और आसपास के क्षेत्रों में चुनाव के बाद हुई हिंसा और सांप्रदायिक तनाव के लिए इस प्रकार के बयान जिम्मेदार हो सकते हैं। इसी शिकायत के आधार पर हेयर स्ट्रीट थाने ने मामला दर्ज किया है। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि पूर्व मुख्यमंत्री की टिप्पणी प्रथम दृष्टया उकसाने वाली, भड़काऊ और सांप्रदायिक प्रकृति की प्रतीत होती है। शिकायत में कहा गया है कि इस तरह के बयान से भय, घृणा और गलतफहमी का माहौल बन सकता है तथा विभिन्न समुदायों के बीच शांति और सौहार्द प्रभावित हो सकता है। शिकायतकर्ता का कहना है कि यदि इस प्रकार की टिप्पणियों को गंभीरता से नहीं लिया गया तो इससे राज्य में सांप्रदायिक सद्भाव और लोकतांत्रिक वातावरण को नुकसान पहुंच सकता है। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि चुनाव के दौरान दिया गया यह बयान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन भी हो सकता है।

भारत-नेपाल के बीच शुरू हुई डिजिटल पेमेंट सर्विस

यूपीआई-एनपीआई लिंक से सीधे खाते में जाएगा पैसा

नई दिल्ली,12 जून 2026। भारत और नेपाल के बीच डिजिटल भुगतान व्यवस्था में एक बड़ी उपलब्धि दर्ज की गई है। दोनों देशों ने क्रॉस-बॉर्डर पीयर-टू-पीयर रेमिटेंस सिस्टम की शुरुआत की है, जिसके तहत अब भारत का यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस और नेपाल का नेशनल पेमेंट्स इंटरफेस आपस में जुड़ गए हैं। इस नई व्यवस्था से दोनों देशों के नागरिक और व्यापारी रियल-टाइम में सुरक्षित और तेज़ डिजिटल भुगतान कर सकेंगे। इस सुविधा को एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड और नेपाल क्लियरिंग हाउस लिमिटेड के सहयोग से लागू किया गया है। अब उपयोगकर्ता मोबाइल नंबर, यूपीआई आईडी या वर्चुअल पेमेंट एड्रेस के जरिए आसानी से पैसे भेज और प्राप्त कर सकेंगे।

ओमान तट हमले पर राहुल गांधी का बड़ा हमला,मोदी सरकार पर उठाए सवाल...

नई दिल्ली,12 जून 2026। ओमान तट के रणनीतिक खाड़ी क्षेत्र में भारतीय चालक दल (क्रू) वाले तीन कमर्शियल जहाजों पर अमेरिकी नौसेना द्वारा किए गए हमलों के बाद पूरे देश में आक्रोश का माहौल है। इस गंभीर अंतरराष्ट्रीय मुद्दे को लेकर अब घरेलू सियासत भी पूरी तरह गरमा गई है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने इस हमले में मारे गए तीन भारतीय नाविकों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए सरकार की विदेश नीति और सुरक्षा रणनीति पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस का स्पष्ट कहना है कि अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में भारतीय नागरिकों की इस तरह हुई मौतों पर केंद्र सरकार अपनी नैतिक और प्रशासनिक जिम्मेदारी से किसी भी कीमत पर बच नहीं सकती है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भारतीय क्रू की मौजूदगी वाले तीन कमर्शियल जहाजों पर अमेरिकी नौसेना द्वारा की गई आक्रामक सैन्य कार्रवाई की कड़े शब्दों में निंदा की है।

उन्होंने इस मुद्दे को लेकर सीधे प्रधानमंत्री को आड़े हाथों लिया। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया और सार्वजनिक मंचों के जरिए मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में महज तीन दिनों के भीतर तीन अलग-अलग व्यापारिक जहाजों पर अमेरिकी सेना द्वारा हमले किए गए।

थाईलैंड की राजकुमारी बज्रकितियाभा का निधन,3 साल कोमा में रहने के बाद तोड़ा दम

थाईलैंड,12 जून 2026। थाईलैंड के शाही परिवार से एक बेहद दुखद और बड़ी खबर सामने आई है। थाईलैंड की लोकप्रिय राजकुमारी बज्रकितियाभा नरेन्द्रदेव्यावती का 47 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वह पिछले लगभग 3 वर्षों से कोमा में थीं और लंबे समय से एक गंभीर जानलेवा बीमारी से बहादुरी से जंग लड़ रही थीं। उनके इस असामयिक निधन पर भारत सरकार ने गहरा शोक व्यक्त किया है। बैंकॉक में स्थित भारतीय दूतावास ने थाई शाही परिवार और वहां की आम जनता के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। भारतीय दूतावास ने अपने आधिकारिक संदेश में कहा कि दुख की इस अत्यंत कठिन घड़ी में भारत के नागरिकों की संवेदनाएं थाईलैंड के राजा,पूरे शाही परिवार और वहां के देशवासियों के साथ हैं। दूतावास ने सामाजिक सेवा, लोक कल्याण और अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के क्षेत्र में राजकुमारी द्वारा दिए गए ऐतिहासिक योगदान को भी याद किया।

नीट री-एग्जाम के नियमों में बड़ा बदलाव,अब मिलेगा ज्यादा समय

नई दिल्ली,12 जून 2026। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट री-एग्जाम की तैयारियां पूरी मुस्तैदी से शुरू कर दी हैं। पेपर लीक विवाद के बाद आयोजित होने जा रही इस परीक्षा को पारदर्शी और छात्र-अनुकूल बनाने के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कई महत्वपूर्ण नीतिगत बदलावों की घोषणा की है। इन सुधारों के अंतर्गत परीक्षा की कॉपी के लेआउट से लेकर समय-सीमा तक में फेरबदल किया गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का मानना है कि इन बदलावों से अभ्यर्थियों को परीक्षा हॉल में बेहतर माहौल मिलेगा और वे बिना किसी मानसिक तनाव के अपना पेपर हल कर सकेंगे।

नीट री-एग्जाम की मुख्य वजह और परीक्षा की नई तिथि : गौरतलब है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा नीट यूजी 2026 परीक्षा का आयोजन देश भर में 3 मई को किया गया था। परीक्षा के सुचारू संचालन के बाद 6 मई को इसकी प्रोविजनल आंसर-की भी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी गई थी। लेकिन इसी दौरान देश के विभिन्न हिस्सों से पेपर लीक होने और अनियमितताओं की खबरें सामने आने लगीं। छात्रों के कड़े विरोध और मामले की

गंभीरता को देखते हुए सरकार ने नीट यूजी परीक्षा 2026 को पूरी तरह रद्द करने का फैसला किया। वर्तमान में इस पूरे पेपर लीक मामले की गहन जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा की जा रही है। इस बीच, प्रभावित उम्मीदवारों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने परीक्षा को दोबारा आयोजित करने का फैसला किया है और अब 21 जून को नीट री-एग्जाम का आयोजन प्रस्तावित किया गया है।

नीट पेपर हल करने के लिए अब मिलेंगे कुल 195 मिनट : समय प्रबंधन को लेकर भी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने छात्रों को एक बहुत बड़ी राहत दी है। अब नीट री-एग्जाम को हल करने के लिए उम्मीदवारों को कुल 195 मिनट का समय दिया जाएगा। इसका मतलब है कि सामान्य परीक्षा अवधि की तुलना में छात्रों को इस बार 15 मिनट का अतिरिक्त समय मिलेगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के अनुसार, पिछले कई वर्षों से छात्रों और विशेषज्ञों की तरफ से यह निरंतर फीडबैक मिल रहा था कि परीक्षा के दौरान कुछ अनिवार्य औपचारिकताओं के कारण उनका मुख्य समय बर्बाद हो जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए परीक्षा का समय बढ़ाकर 195 मिनट किया गया है। यह री-एग्जाम दोपहर 2:00 बजे से शुरू होकर शाम 5:15 बजे तक संचालित किया जाएगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने परीक्षार्थियों की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उत्तर पुस्तिका यानी एग्जाम कॉपी के पारंपरिक लेआउट में अमूलचूल परिवर्तन किया है। अब तक की व्यवस्था के अनुसार, अभ्यर्थियों को परीक्षा के दौरान रफवर्क करने के लिए काफी सीमित स्थान मिलता था, जिससे भौतिकी और रसायन विज्ञान के न्यूमेरिकल हल करने में भारी परेशानी होती थी। छात्रों की इसी समस्या को दूर करने के लिए अब कॉपी में रफवर्क के पेजों की संख्या को सीधे दोगुना कर दिया गया है।

अब 'कॉकरोच जनता पार्टी' राजस्थान में भरेगी हुंकार

जयपुर में प्रदर्शन का ऐलान

जयपुर,12 जून 2026। राजस्थान की राजधानी जयपुर में आगामी 15 जून को 'कॉकरोच जनता पार्टी' का प्रदर्शन होगा। देश की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने और युवाओं के रोजगार से जुड़े मुद्दों को उठाने के लिए 'कॉकरोच जनता पार्टी' की राजस्थान इकाई ने एक बड़े आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। जयपुर के गवर्नमेंट हॉस्टल स्थित प्रसिद्ध शहीद स्मारक पर 15 जून को यह राज्य स्तरीय प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। इस विरोध-प्रदर्शन की तैयारियों को लेकर शुक्रवार को जयपुर में कॉकरोच जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। रांका ने साफ किया कि यह कोई पारंपरिक राजनीतिक विरोध नहीं है, बल्कि यह देश की रीढ़ यानी हमारे छात्र समुदाय और युवा वर्ग के भविष्य को बचाने की एक बेहद गंभीर और जरूरी मुहिम है।

संपादकीय

कानूनों का दुरुपयोग रोकने का समय

हाल में देश की शीर्ष अदालत ने एक मामले में महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए एक ऐसी चिंताजनक प्रवृत्ति की ओर ध्यान आकर्षित किया, जो केवल न्याय व्यवस्था ही नहीं,बल्कि पूरे समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय है। न्यायालय ने कहा,वैवाहिक अथवा व्यावसायिक संबंधों में जुड़े पक्षकार प्रतिशोध की भावना से एक-दूसरे के विरुद्ध आपराधिक प्रकृति के तुच्छ एवं दुर्भावनापूर्ण दावे करने तथा आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। वे अनैतिक और कुटिल उपायों का सहारा लेते हैं। अनेक मामलों में कानून और पुलिस का सहारा न्याय प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि दूसरे पक्षकार तथा उसके परिवारजनों पर दबाव बनाने, उन्हें परेशान करने तथा प्रतिशोध लेने के उद्देश्य से लिया जाता है। यह सब पक्षकार और उसके परिवारजनों के प्रति घृणा और तिरस्कार की भावना से प्रेरित होकर किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय की यह चिंता निराधार नहीं है।

वैवाहिक विवादों में झूठे और दुर्भावनापूर्ण मुकदमों की प्रवृत्ति को लेकर समय-समय पर न्यायालयों ने गंभीर टिप्पणियां की हैं। दहेज उत्पीड़न,वैवाहिक क्रूरता,घरेलू हिंसा तथा अन्य कानूनी प्रविधानों के अंतर्गत ऐसे मामले तमाम सामने आए हैं,जिनमें आरोप न्यायिक परीक्षण में सिद्ध नहीं हो सके। कई बार सामान्य,अस्पष्ट और व्यापक आरोपों के आधार पर पूरे परिवार को मुकदमेबाजी के दायरे में खड़ा कर दिया जाता है।

यह सच है कि महिलाओं के विरुद्ध होने वाली हिंसा, दहेज उत्पीड़न और भेदभाव की समस्या वास्तविक है तथा उससे संघर्ष करना किसी भी सभ्य समाज का दायित्व है,किंतु भारतीय समाज की चुनौती केवल इतनी भर नहीं है। सत्य यह भी है कि अनेक पुरुष झूठे आरोपों,दुर्भावनापूर्ण मुकदमों और लंबी न्यायिक प्रक्रियाओं के कारण मानसिक,सामाजिक और आर्थिक पीड़ा का सामना कर रहे हैं। पुरुषों की समस्याएं आज भी अपेक्षित सामाजिक और विधिक विमर्श का विषय नहीं बन सकी हैं।

परिणामस्वरूप अनेक बार उनकी पीड़ा को या तो गंभीरता से लिया ही नहीं जाता अथवा उसे सामाजिक विमर्श का वैध विषय नहीं माना जाता। यही कारण है कि 22 जनवरी, 2025 को 'ज्योति उर्फ किट्टू बनाम राज्य' मामले में न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा को यह टिप्पणी करनी पड़ी कि यह धारणा कि वैवाहिक संबंधों में केवल महिलाएं ही शारीरिक अथवा मानसिक क्रूरता की शिकार होती हैं और इसके कोई अपवाद नहीं हैं,जीवन की कठोर वास्तविकताओं के विपरीत हो सकती है। न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में कहा था,जिस प्रकार महिलाएं क्रूरता और हिंसा से संरक्षण की अधिकारिणी हैं, उसी प्रकार पुरुष भी विधि के अंतर्गत समान सुरक्षा पाने के अधिकारी हैं।

लंबे समय तक यह माना जाता रहा कि कोई भी महिला अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा और सम्मान को दांव पर लगाकर दुष्कर्म,यौन उत्पीड़न की मिथ्या शिकायत नहीं करेगी। यही कारण था कि ऐसे आरोपों को सामान्यतः विश्वसनीयता के साथ देखा जाता था। इस संदर्भ में गत वर्ष केरल उच्च न्यायालय ने कहा था कि बदलते सामाजिक परिदृश्य में इस धारणा को यांत्रिक रूप से अनुसरण नहीं किया जा सकता कि केवल आरोप लगाए जाने मात्र से उसकी सत्यता स्वतः सिद्ध हो जाती है। न्यायालय ने माना कि यद्यपि ऐसे मामले अपवादस्वरूप हो सकते हैं,तथापि कुछ प्रकरणों में गंभीर आरोप प्रतिशोध, दबाव या अन्य स्वार्थपूर्ण उद्देश्यों से भी लगाए गए हैं। इसलिए किसी भी आरोप की सत्यता का निर्धारण पूर्वधारणाओं से नहीं,बल्कि तथ्यों और साक्ष्यों की कसौटी पर ही किया जाना चाहिए। वास्तव में समस्या का मूल कारण अधिकार नहीं,बल्कि अधिकार और उत्तरदायित्व के बीच बिगड़ता संतुलन है।

किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में अधिकारों का संरक्षण आवश्यक है, किंतु उतना ही आवश्यक यह भी है कि उन अधिकारों के प्रयोग के साथ जवाबदेही भी सुनिश्चित हो। जब किसी कानून का उपयोग संरक्षण के स्थान पर प्रतिशोध, दबाव अथवा व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति का माध्यम बनने लगे,तो उसका प्रभाव केवल संबंधित पक्षों तक सीमित नहीं रहता,बल्कि न्याय व्यवस्था की विश्वसनीयता को भी प्रभावित करता है। देशभर में ऐसे अनेक मामले सामने आए हैं, जिनमें वर्षों तक न्यायिक प्रक्रिया का सामना करने के पश्चात आरोप असत्य अथवा प्रमाणित न हो पाने वाले सिद्ध हुए।

भारत-बांग्लादेश संबंधों में बढ़ता अविश्वास

डॉ .सत्यवान सौरभ
भिवानी,हरियाणी

भारत और बांग्लादेश के संबंध दक्षिण एशिया की कूटनीति में विशेष महत्व रखते हैं। वर्ष 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता के समय भारत ने जिस प्रकार राजनीतिक,सैन्य और मानवीय सहयोग प्रदान किया, उसने दोनों देशों के बीच मैत्री और विश्वास की मजबूत नींव रखी। पिछले पाँच दशकों में व्यापार, सुरक्षा,ऊर्जा,संपर्क,जल संसाधन और सांस्कृतिक आदान-प्रदान जैसे अनेक क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। भारत की पड़ोसी प्रथम नीति तथा बांग्लादेश की विकासोन्मुख विदेश नीति ने भी संबंधों को नई ऊँचाइयाँ प्रदान की हैं। इसके बावजूद हाल के वर्षों में दोनों देशों के संबंधों में तनाव और अविश्वास के संकेत दिखाई दिए हैं। यह स्थिति इस तथ्य को रेखांकित करती है कि पड़ोसी देशों के साथ संबंध केवल रणनीतिक हितों से संचालित नहीं होते, बल्कि उनमें संवेदनशीलताओं, जनभावनाओं और पारस्परिक सम्मान का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है।

भारत और बांग्लादेश लगभग 4,096 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं, जो भारत की किसी भी पड़ोसी देश के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक, भाषाई और ऐतिहासिक संबंध मौजूद हैं। पिछले एक दशक में भूमि सीमा समझौता,सीमा प्रबंधन,आतंकवाद विरोधी सहयोग,ऊर्जा व्यापार तथा क्षेत्रीय संपर्क परियोजनाओं में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई है। बांग्लादेश आज भारत का एक प्रमुख व्यापारिक साझेदार है और भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र को मुख्य भूमि से जोड़ने में भी उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए दोनों देशों के बीच विश्वास और सहयोग केवल द्विपक्षीय नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की स्थिरता और समृद्धि के लिए आवश्यक है।

हाल के समय में बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति में हुए बदलावों ने द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावित किया है। सत्ता परिवर्तन,राजनीतिक अस्थिरता और विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच प्रतिस्पर्धा के कारण भारत की भूमिका को लेकर अलग-अलग धारणाएँ विकसित हुई हैं। बांग्लादेश के कुछ राजनीतिक समूहों में यह धारणा बनी कि भारत किसी विशेष राजनीतिक शक्ति के प्रति अधिक सहानुभूति रखता है, जबकि भारत अपनी ओर से स्थिरता और विकास को प्राथमिकता देने की बात करता रहा है। इस प्रकार की धारणाएँ चाहे तथ्यात्मक रूप से सही हों या नहीं, वे विश्वास के वातावरण को प्रभावित करती हैं और संबंधों में मनोवैज्ञानिक दूरी उत्पन्न करती हैं।

तीस्ता नदी के जल बँटवारे का मुद्दा लंबे समय से दोनों देशों के बीच एक प्रमुख विवाद का विषय बना हुआ है। बांग्लादेश के लिए तीस्ता नदी का जल कृषि और आजीविका की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। कई वर्षों से प्रस्तावित समझौता विभिन्न कारणों से लंबित है,जिससे बांग्लादेश में यह भावना विकसित हुई है कि उसकी चिंताओं को अपेक्षित प्राथमिकता नहीं मिल रही। भारत की संघीय व्यवस्था में राज्यों की भूमिका भी इस विषय को जटिल बनाती है, लेकिन समाधान में देरी ने अविश्वास को बढ़ावा दिया है। जल संसाधनों के न्यायसंगत और टिकाऊ प्रबंधन के बिना दीर्घकालिक विश्वास निर्माण कठिन प्रतीत होता है।

सीमा संबंधी मुद्दे भी संबंधों में तनाव का कारण बने हैं। तस्करी,अवैध आव्रजन और सीमा सुरक्षा की चुनौतियों के कारण कई बार सीमा पर अप्रिय घटनाएँ हुई हैं। नागरिक हताहतों की घटनाओं ने बांग्लादेश में व्यापक प्रतिक्रिया उत्पन्न की है और भारत की छवि पर भी प्रभाव डाला है। यद्यपि दोनों देशों की सीमा सुरक्षा एजेंसियाँ समन्वय बढ़ाने के प्रयास कर रही हैं, फिर भी ऐसी घटनाएँ आम लोगों के मन में नकारात्मक भावनाएँ पैदा करती हैं। पड़ोसी देशों के बीच सीमा केवल सुरक्षा का विषय नहीं होती,बल्कि मानवीय और सामाजिक संबंधों से भी जुड़ी होती है।

नागरिकता संशोधन अधिनियम और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर जैसे मुद्दों ने भी बांग्लादेश में कुछ आशंकाएँ उत्पन्न कीं। यद्यपि भारत ने बार-बार स्पष्ट किया कि ये उसकी आंतरिक नीतियाँ हैं, फिर भी बांग्लादेश में यह चिंता व्यक्त की गई कि इनका अप्रत्यक्ष प्रभाव भविष्य में दोनों देशों के संबंधों पर पड़ सकता है। अंतरराष्ट्रीय संबंधों में नीतियों की वास्तविकता के साथ-साथ उनकी सार्वजनिक धारणा भी महत्वपूर्ण होती है और यही कारण है कि ऐसे मुद्दे कभी-कभी कूटनीतिक विमर्श का हिस्सा बन जाते हैं।

दक्षिण एशिया में चीन की बढ़ती सक्रियता भी भारत-बांग्लादेश संबंधों को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। बांग्लादेश ने अपनी विकास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चीन सहित कई देशों के साथ आर्थिक और अवसंरचनात्मक सहयोग बढ़ाया है। भारत के लिए यह स्वाभाविक चिंता का विषय है कि क्षेत्र में किसी बाहरी शक्ति का अत्यधिक प्रभाव उसके रणनीतिक हितों को प्रभावित कर सकता है। दूसरी ओर बांग्लादेश अपनी विदेश नीति में संतुलन बनाए रखते हुए विभिन्न देशों से निवेश और तकनीकी सहयोग प्राप्त करना चाहता है। इस स्थिति में दोनों देशों के लिए पारदर्शिता और संवाद अत्यंत आवश्यक हो जाते हैं।

व्यापारिक असंतुलन भी अविश्वास के कारकों में शामिल है। यद्यपि द्विपक्षीय व्यापार लगातार बढ़ रहा है,लेकिन इसका लाभ अपेक्षाकृत अधिक भारत को मिलता हुआ दिखाई देता है। बांग्लादेश लंबे समय से भारतीय बाजार में अपने उत्पादों की बेहतर पहुँच तथा गैर-शुल्क बाधाओं में कमी की मांग करता रहा है। आर्थिक संबंधों में असंतुलन की भावना यदि लंबे समय तक बनी रहे तो वह राजनीतिक संबंधों को भी प्रभावित कर सकती है। इसलिए आर्थिक साझेदारी को अधिक संतुलित और समावेशी बनाना समय की आवश्यकता है।

सोशल मीडिया और डिजिटल माध्यमों ने भी संबंधों को प्रभावित किया है। आज गलत सूचनाएँ,भ्रामक प्रचार और राष्ट्रवादी भावनाओं को भड़काने वाली सामग्री बहुत तेजी से फैलती है। कई बार छोटी घटनाएँ भी डिजिटल मंचों पर बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत की जाती हैं, जिससे दोनों देशों के नागरिकों के बीच गलतफहमियाँ उत्पन्न होती हैं। ऐसे वातावरण में सरकारों और मीडिया संस्थानों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वे तथ्यपरक संवाद को बढ़ावा दें और दुष्प्रचार पर प्रभावी नियंत्रण रखें।

भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह अपने रणनीतिक हितों और पड़ोसी देशों की संवेदनशीलताओं के बीच संतुलन स्थापित करे। एक बड़ी क्षेत्रीय शक्ति होने के कारण भारत की नीतियों का प्रभाव उसके पड़ोसियों पर स्वाभाविक रूप से पड़ता है। इसलिए केवल राष्ट्रीय हितों पर केंद्रित दृष्टिकोण पर्याप्त नहीं है;पड़ोसी देशों की आशंकाओं और अपेक्षाओं को समझना भी उतना ही आवश्यक है। इसी प्रकार बांग्लादेश को भी यह समझना होगा कि भारत की सुरक्षा चिंताएँ, विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्र से संबंधित प्रश्न,उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। दोनों देशों को एक-दूसरे की वैध चिंताओं का सम्मान करना होगा।

विश्वास बहाली के लिए सबसे पहले लंबित मुद्दों के समाधान की दिशा में ठोस पहल आवश्यक है। तीस्ता जल समझौते को प्राथमिकता देकर दोनों देश एक सकारात्मक संदेश दे सकते हैं। सीमा प्रबंधन में मानवीय दृष्टिकोण अपनाना,संयुक्त गश्त और तकनीकी सहयोग को बढ़ाना भी आवश्यक है। व्यापारिक असंतुलन को कम करने के लिए बांग्लादेशी उत्पादों को भारतीय बाजार में अधिक अवसर दिए जा सकते हैं। ऊर्जा,परिवहन और संपर्क परियोजनाओं को गति देकर दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को और अधिक परस्पर निर्भर बनाया जा सकता है।

उच्च स्तरीय राजनीतिक संवाद को नियमित और संस्थागत स्वरूप देना भी आवश्यक है। जब देशों के शीर्ष नेतृत्व के बीच निरंतर संवाद बना रहता है, तब गलतफहमियों की संभावना कम हो जाती है। साथ ही शिक्षा,संस्कृति,खेल, मीडिया और पर्यटन के माध्यम से लोगों के बीच संपर्क बढ़ाना चाहिए। सरकारों के बीच विश्वास जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण नागरिकों के बीच विश्वास भी है। सांस्कृतिक निकटता दोनों देशों की सबसे बड़ी शक्ति है और इसे संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रभावी रूप से उपयोग किया जा सकता है।

क्षेत्रीय मंचों जैसे बिंस्टेक् और बीबिन के माध्यम से सहयोग को बढ़ावा देना भी उपयोगी होगा। साझा आर्थिक और रणनीतिक हितों पर आधारित क्षेत्रीय सहयोग अविश्वास को कम करने में सहायक हो सकता है। जलवायु परिवर्तन,आपदा प्रबंधन, समुद्री सुरक्षा और ऊर्जा सहयोग जैसे क्षेत्रों में संयुक्त प्रयास दोनों देशों को और निकट ला सकते हैं।

अंततः भारत और बांग्लादेश के संबंध केवल दो देशों के बीच की साझेदारी नहीं हैं,बल्कि इतिहास, संस्कृति,भाषा,भूगोल और साझा संघर्षों से निर्मित एक विशेष संबंध हैं। हाल के वर्षों में उत्पन्न तनाव और अविश्वास यह अवश्य दर्शाते हैं कि पड़ोसी देशों के साथ संबंधों में संवेदनशीलताओं और रणनीतिक हितों के बीच संतुलन बनाए रखना कितना आवश्यक है। संवाद, सहयोग,पारस्परिक सम्मान और साझा विकास की भावना के आधार पर दोनों देश वर्तमान चुनौतियों को अवसर में बदल सकते हैं। यदि भारत और बांग्लादेश विश्वास की नई नींव पर अपने संबंधों का पुनर्निर्माण करते हैं, तो न केवल द्विपक्षीय संबंध अधिक मजबूत होंगे,बल्कि दक्षिण एशिया में शांति,स्थिरता और समृद्धि का मार्ग भी अधिक प्रशस्त होगा।

स्त्री नहीं,सोच घर बनाती और बिगाड़ती है...

कृति आर.के.जैन
बड़वानी,मध्यप्रदेश

यह कौन-सा नियम है जहां दोष पहले से तय होता है?

परिवार की सफलता और विफलता का बोझ केवल महिलाओं पर क्यों?

हमारे समाज में कुछ फैसले ऐसे हैं जिन पर कभी बहस नहीं हुई, फिर भी वे अंतिम सत्य मान लिए गए हैं। उन्हीं में से एक है–घर बनाती भी स्त्री है और और घर बिगाड़ती भी वही है। परिवार में सुख, संस्कार और रिश्तों में मधुरता हो तो कहा जाता है–बहू बहुत अच्छी मिली है। लेकिन तनाव या विघटन होते ही आरोप सबसे पहले उसी पर आता है, मानो घर किसी एक व्यक्ति द्वारा चलने वाली व्यवस्था हो। यह केवल सामाजिक पूर्वाग्रह नहीं,बल्कि वह मानसिकता है जिसने स्त्री के त्याग को कर्तव्य और उसकी पीड़ा को नियति मान लिया है। प्रश्न यह नहीं कि स्त्री की भूमिका महत्वपूर्ण है या नहीं–वह निस्संदेह है, बल्कि यह है कि क्या वह अकेली जिम्मेदार है? यदि घर बनाना सामूहिक प्रक्रिया है, तो उसका बिगड़ना भी सामूहिक विफलता है। फिर हर बार कठघरे में केवल स्त्री ही क्यों? यह प्रश्न परिवार के भविष्य से जुड़ा है।

घर एक व्यवस्था है, कोई व्यक्ति नहीं...

हम अक्सर घर को चार दीवारों और छत का नाम मान लेते हैं,जबकि वह भावनाओं,संघर्षों और रिश्तों से बनी एक जीवंत व्यवस्था है। वहां भावनाएं, उम्मीदें,समझौते और रिश्ते सभी रहते हैं। इसमें माता,पिता,बच्चे और बुजुर्ग सभी की भूमिका समान रूप से महत्वपूर्ण होती है। फिर भी यह धारणा बना ली गई है कि घर की सफलता का श्रेय पूरे परिवार को मिलेगा,लेकिन उसकी विफलता का दोष केवल स्त्री पर जाएगा। क्या कोई खेत केवल बारिश से लहलहाता है,क्या कोई वृक्ष केवल जड़ों से खड़ा रहता है,क्या कोई नदी केवल एक स्रोत से बहती है? जब हर प्राकृतिक संरचना सामूहिक योगदान से बनती है, तो परिवार जैसी जटिल संस्था की जिम्मेदारी एक ही व्यक्ति पर कैसे डाली जा सकती है?

लक्ष्मी बनाकर बोझ क्यों?

भारतीय समाज ने स्त्री को सम्मान देने के लिए उसे देवी,लक्ष्मी और अन्नपूर्णा कहा, लेकिन यह सम्मान कई बार बोझ बन गया। देवी बना देने से उसके इंसान होने का अधिकार सीमित हो गया–उसके थकने,रोने,गलती करने और अपनी इच्छाएँ रखने की गुंजाइश कम हो गई। उससे अपेक्षा की गई कि वह हर परिस्थिति में मुस्कुराए, सबको जोड़े रखे और स्वयं को सबसे अंत में रखे। विडंबना यह है कि जिस सम्मान के कारण उसे ऊँचा स्थान दिया गया, उसी पर इतना दायित्व डाल दिया गया कि वह दबने लगी, और जब वह थक गई तो कहा गया–घर संभाल नहीं पाई।

नई भूमिकाएँ,पुराने बोझ

आज की स्त्री केवल रसोई तक सीमित नहीं है;वह डॉक्टर,इंजीनियर, शिक्षक, अधिकारी और उद्यमी बनकर परिवार की आर्थिक रीढ़ भी बन रही है। फिर भी जिम्मेदारियाँ उसके साथ समान रूप से साझा नहीं की गई हैं–दफ्तर से लौटने के बाद भी रसोई,बच्चों की पढ़ाई, रिश्तेदारियों का निर्वाह और बुजुर्गों की देखभाल अधिकतर उसी पर बनी रहती है। समाज ने उसके कंधों पर नए दायित्व जोड़ दिए,लेकिन पुराने बोझ कम नहीं किए। यह व्यवस्था उसे सशक्त नहीं बनाती,बल्कि धीरे-धीरे भीतर से थका देती है। और जब यह थकान या असंतोष सामने आता है, तो उसे स्त्री का स्वभाव कहकर नजरअंदाज कर दिया जाता है।

समस्या स्त्री नहीं,सोच है...

दरअसल समस्या स्त्री या पुरुष नहीं, बल्कि सोच है–जो घर की जिम्मेदारी स्त्री पर और अधिकार पुरुष पर मान लेती है,और त्याग को केवल स्त्री का गुण समझती है। यही सोच पुरुष की अनुपस्थिति को मजबूरी और स्त्री की थकान को कमजोरी मानती है। घर मतभेद या आर्थिक संकट से नहीं टूटते, बल्कि तब टूटते हैं जब संवाद और सम्मान समाप्त हो जाता है और लोग परिस्थितियों से लड़ने के बजाय एक-दूसरे से लड़ने लगते हैं। इसलिए किसी घर को बचाना है तो सबसे पहले सोच बदलनी होगी।

साझेदारी से सशक्त परिवार

सशक्त परिवार की पहचान विवादों की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि उनका मिलकर समाधान है। जहां पति समझे कि परिवार केवल आर्थिक संसाधनों से नहीं चलता,पत्नी महसूस करे कि उसके संघर्षों को समझा जा रहा है,बच्चे जिम्मेदारियां सीखें और बुजुर्ग अनुभव साझा करें,दबाव नहीं। परिवार तब मजबूत होता है जब हर सदस्य स्वयं को सहभागी माने, बोझ नहीं। सम्मान बड़े उपहारों से नहीं,बल्कि रोजमर्रा के व्यवहार–एक धन्यवाद,एक क्षमा, संवेदन शील संवाद और एक-दूसरे की थकान को समझने से आता है। यही छोटे प्रयास बड़े संकटों को भी कम कर देते हैं।

उंगली नहीं,आईना उठाओ

जब भी कोई घर टूटे,समाज को अपनी पुरानी आदत बदलनी होगी। हर बार स्त्री को दोषी ठहराने से न घर बचते हैं,न रिश्ते। घर टूटने के कारण गहरे हैं–अहंकार,संवादहीनता,असमान जिम्मेदारियां और सम्मान की कमी। स्त्री घर की धुरी हो सकती है,पर वह अकेला पहिया नहीं है; परिवार एक रथ है जिसे सभी मिलकर चलाते हैं। एक पहिया टूट जाए तो रथ नहीं चलता। लेकिन यदि बाकी पहिए भी अपनी जिम्मेदारी भूल जाएं तो फिर दोष केवल एक पहिए का नहीं होता। समय है कि स्त्री को देवी नहीं, इंसान मानकर साझेदारी दी जाए। घर एक के त्याग से नहीं, सबके सहयोग से बनता है,और उसके बिगड़ने का दोष भी किसी एक पर नहीं डाला जा सकता। समाज जब यह सरल सत्य स्वीकार करेगा,तभी परिवार अधिक न्यायपूर्ण,मानवीय और मजबूत बनेंगे। तब घरों में कटघरे नहीं,संवाद होंगे; आरोप नहीं,सहभागिता होगी। तब समझ आएगा कि घर बनाने वाली केवल स्त्री नहीं, बल्कि वह सोच है जो मैं से ऊपर उठकर हम में विश्वास करती है।

बेईमान बहन-भाई और सौतेली मां का ज़ुल्म

डॉ. मुश्ताक़ अहमद शाह सहज़,हरदा (मध्य प्रदेश)

वालिद साहब (पिताजी) के इंतक़ाल को अभी चंद ही महीने हुए थे कि घर की फज़ा (माहौल) बिल्कुल बदल गई। बड़ा बेटा, जो हमेशा से अपने वालिद का फ़रमाबरदार और पूरे ख़ानदान का सहारा था,अचानक अपने ही घर में अकेला और बेबस हो गया। वालिद की वफ़ात के बाद आमिर ने अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने सारे फ़र्ज़ निभाए,जनाज़े के अख़राज़ात (ख़र्चों) से लेकर सौतेली मां और छोटे बहन-भाइयों के अख़राज़ात तक,उसने कभी किसी चीज में कमी नहीं आने दी।

लेकिन दूसरी तरफ़,सौतेली मां के दिल में कुछ और ही चल रहा था। आमिर के सगे बहन-भाई,जो अब तक उसके साए में पले-बढ़े थे,अपनी मां की बातों में आकर बेईमान हो चुके थे। इन सबकी नजरें अब सिर्फ़ वालिद की छोड़ी हुई जायदाद और कारोबार पर थीं। सौतेली मां ने आहिस्ता-आहिस्ता आमिर के ख़िलाफ़ जाल बुनना शुरू कर दिया। वह हर वक्त आमिर के छोटे बहन-भाइयों के कान भरती कि,दामादों के कहने पर,अगर आमिर को उसका हिस्सा मिल गया,तो तुम लोगों के हाथ कुछ नहीं आएगा। यह तुम्हारा सगा भाई नहीं है, यह सब कुछ अकेला हड़पना चाहता है। आमिर को तो इस सच्चाई का इल्म (पता) भी न था कि वह इस घर का सगा नहीं बल्कि सौतेली मां का बड़ा बेटा है। मगर उसने तो मोहब्बत और फ़र्ज़ निभाने में कभी सौतेले और सगे का फ़र्क़ जाना ही नहीं था। वह दिन-रात मेहनत करके कारोबार को संभाल रहा था ताकि घर का चूल्हा जलता रहे। लेकिन साज़िशें इस हद तक बढ़ गईं कि आमिर को बताए बग़ैर बैंक अकाउंट्स और दुकान के कागज़ात अपने नाम करवाने की कोशिशें शुरू कर दी गईं,जहां आमिर दिन-रात अपना ख़ून-पसीना बहाता था।

घर के हर फ़ैसले से आमिर को दूर रखा जाने लगा। यहां तक कि रात के खाने पर भी उसे अकेला छोड़ दिया जाता। आमिर के सगे बहन-भाई जिन्हें उसने अपनी औलाद की तरह पाला था, अब उससे सीधे मुंह बात भी नहीं करते थे। दामादों की मुनाफ़कत (मक्कारी) और झूठा तक़्वा (परहेजगारी) दखल बढ़ता जा रहा था,

इस पूरे घर को बर्बाद करने और आग लगाने में सबसे बड़ा हाथ बड़े दामाद का था, जिसकी मुनाफ़क़त की कोई हद न थी। वह शख़्स हज पर नहीं गया था, उसने जिंदगी में कभी हज का फ़रीज़ा अदा नहीं किया था, लेकिन मुआशरे (समाज) में अपनी झूठी इज़्ज़त बनाने के लिए वह ख़ुद को मस्जिदों में हाजी साहब कहलवाता था। सारा दिन नाकारा बैठकर दूसरों की कमाई पर पलने वाले इन दामादों का वाहिद (एकमात्र) काम दिन-रात घर में आग लगाना और सौतेली मां को आमिर के ख़िलाफ़ भड़काना था।

वह बड़ा दामाद पांच वक्त का नमाजी था,बाक़ायदगी से मस्जिद जाता, तहमत और टोपी पहनकर अपने तक़्वे की नुमाइश (दिखावा) करता,लेकिन उसका दिल खौफ़-ए-ख़ुदा (ईश्वर के डर) से बिल्कुल ख़ाली था। उसे इस बात का ज़रा भी डर नहीं था कि वह जिस रब के सामने सजदा कर रहा है, वह उसके दिल के खोट और उसकी मकारियों से वाकिफ है। वह नमाज़ें पढ़कर घर आता और आमिर के ख़िलाफ़ ज़हर उगलना शुरू कर देता।

सौतेली मां इस लालच और पट्टी में इतनी अंधी हो चुकी थी कि वह यह भी भूल गई कि बुढ़ापा सब पर आता है,और जिस बड़े बेटे को वह आज घर से निकाल रही है,कल वही उसका सच्चा सहारा बन सकता था।

फिर एक दिन सब्र और दरकिनार का लम्हा भी आही गया।

एक शाम जब आमिर थका-हारा दुकान से लौटा,तो उसने देखा कि घर के बैठक में सौतेली मां और उसके बहन-भाई एक साथ बैठे कागज़ात पर दस्तख़त (हस्ताक्षर) कर रहे थे। जब आमिर ने अंदर जाकर पूछा कि यह सब क्या हो रहा है, तो सौतेली मां ने सर्द लहज़े में कहा।

तुम्हारे वालिद ने मरने से पहले ज़बानी वसीयत की थी कि यह घर और कारोबार सिर्फ़ मेरे बच्चों का होगा। तुम अब अपनी राह देखो,क्योंकि तुम्हारा इस घर पर कोई हक नहीं है। और सुनो,तुम मेरे सगे बेटे भी नहीं हो! आमिर के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। यह इंकशाफ़ (ख़ुलासा) कि वह सौतेला है, उसे उतना नहीं तड़पा गया जितना अपनों की बेवफाई का दर्द तड़पा गया। उसने अपने भाइयों और बहनों की तरफ़ देखा,जिनके हुक़ूक़ के लिए उसने अपनी जवानी दांव पर लगा दी थी,लेकिन उन सब ने अपनी नजरें झुका लीं। कोई एक भी आमिर के हक में न बोला,क्योंकि बेईमानी और लालच उनके दिलों में घर कर चुकी थी।

आमिर ने कोई झगड़ा नहीं किया, न ही कोई बददुआ दी। उसने आसमान की तरफ़ देखा,अपने मरहूम (स्वर्गीय) वालिद की रूह को याद किया जिसने उसे हमेशा डटकर जीना सिखाया था,और ख़ामोशी से अपना मुख़्तसर (छोटा सा) सामान समेटकर उस घर से निकल गया जिसे उसने अपने ख़ून-पसीने से सींचा था।

घर से निकलने के बाद आमिर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह पढ़ा-लिखा और बासलाहियत (प्रतिभावान) था। उसने दिन-रात एक कर दिए, अपनी मेहनत और ईमानदारी के बल-बूते पर उसने न सिर्फ़ बेपनाह नाम कमाया बल्कि बहुत सी जायदाद और दौलत भी बनाई। उसने अपने रब पर भरोसा रखा और एक पुरसुकून (शांत),इज्ज़तदार दुनिया बसा ली।

सूचना
समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटारा अम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।
–सम्पादक

नेताओं की मजबूरी पर वफादारी का चोला

संजय सक्सेना,लखनऊ,उत्तरप्रदेश

राजनीति में वफादारी और मजबूरी के बीच की लकीर अक्सर इतनी पतली होती है कि आम आदमी तो क्या,खुद नेता भी भूल जाते हैं कि वे किस तरफ खड़े हैं। तृणमूल कांग्रेस के तीन सांसदों शत्रुघ्न सिन्हा, कीर्ति आजाद और बाबुल सुप्रियो की कहानी इसी सच्चाई की एक जीती-जागती मिसाल है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी की करारी हार के बाद जब पार्टी के करीब बीस सांसद बगावत पर उतर आए और मोदी सरकार के साथ खे` होने का एलान कर दिया,तब यही तीनों नेता दीदी यानी ममता बनर्जी की वफादारी का ढिंढोरा पीटने में लगे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा ने बयान दिया कि वे ममता जी के साथ हैं और हमेशा टीएमसी में ही रहेंगे। कीर्ति आजाद ने भी संकट की इस घे ी में ममता बनर्जी का हाथ थामे रखने का एलान किया। लेकिन जो बात इन बयानों के पीछे छिपी है,वह यह है कि इन नेताओं के पास फिलहाल कोई और चारा है भी नहीं। सबसे पहले बात शत्रुघ्न सिन्हा की। शत्रुघ्न सिन्हा ने भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ जाकर भाजपा छोड़ी थी,लेकिन भाजपा में आज भी उनके कई पुराने मित्र मौजूद हैं। यही कारण है कि जब टीएमसी में तूफान आया तो उनकी चुप्पी ने सबको चौंकाया। वे न बागी खेमे में नजर आए,न ममता के साथ खुलकर। लेकिन जब यह साफ हो गया कि भाजपा उनके लिए अपने दरवाजे खोलने के मूड में नहीं है,तो उनकी कथित वफादारी की घोषणा सामने आ गई।

बता दें,शत्रुघ्न सिन्हा लंबे समय तक भाजपा के चमकते सितारे रहे। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में वे केंद्रीय मंत्री रहे। लेकिन धीरे-धीरे पार्टी में उनकी पूछ कम होती गई। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब भाजपा ने नई करवट ली तो पुरानी पीढ़ी के कई नेताओं को हाशिये पर धकेल दिया गया। शत्रुघ्न सिन्हा पार्टी में घुट-घुटकर रहते रहे और अंदर ही अंदर असंतोष पकता रहा। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने भाजपा से नाता तो लिया और कांग्रेस के टिकट पर पटना साहिब से चुनाव लड़े,लेकिन हार गए। इसके बाद उनका राजनीतिक सफर भटकाव का शिकार रहा और अंततः वे तृणमूल कांग्रेस में आ गए। 2024 के लोकसभा चुनाव में शत्रुघ्न सिन्हा आसनसोल से करीब साठ हजार वोटों से जीते। लेकिन यह जीत उनकी अपनी नहीं,ममता बनर्जी की लहर थी। अब जब वही लहर उतर रही है, तो उनके पास लौटने के लिए कोई ठिकाना नहीं है। कीर्ति आजाद की कहानी तो और भी दिलचस्प है। दिसंबर 2015 में दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ में कथित अनियमितताओं तथा भ्रष्टाचार को लेकर तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली को खुले तौर पर निशाना बनाने के लिए उन्हें भाजपा से निलंबित कर दिया गया था। वे 2018 में कांग्रेस में शामिल हो गए थे। कांग्रेस ने उन्हें 2019 में धनबाद से टिकट दिया,लेकिन वहां भी उन्हें मुंह की खानी पड़ी। इसके बाद 2024 में वे तृणमूल कांग्रेस के जरिये बर्धमान-दुर्गापुर से लोकसभा पहुंचे।

कुछ सवाल भी छोड़ गई 10 करोड़ के गांजे की बरामदगी...

1941 किलो गांजा पकड़ा,लेकिन सरहद तक पहुंचा कैसे?

बसंतपुर पुलिस की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई,10 करोड़ का गांजा,50 लाख का ट्रक जब्त,दो तस्कर गिरफ्तार

-संवाददाता-
बलरामपुर/बसंतपुर,12 जून 2026 (घटती-घटना)।

बलरामपुर जिले की बसंतपुर पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए 1941.110 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। पुलिस ने इस मामले में उत्तर प्रदेश के दो अंतरराज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है तथा तस्करी में प्रयुक्त करीब 50 लाख रुपए कीमत का टाटा ट्रक भी जब्त किया है। बरामद गांजा की अनुमानित कीमत लगभग 10 करोड़ रुपए बताई जा रही है। कुल जब्त मशरूका की कीमत साढ़े 10 करोड़ रुपए से अधिक आंकी गई है। पुलिस की यह कार्रवाई निश्चित रूप से सराहनीय है,लेकिन इसके साथ ही कई गंभीर सवाल भी खड़े हो गए हैं,जिनका जवाब जनहित में मिलना आवश्यक है।

देर रात तकनीकी सूचना पर हुई कार्रवाई...

पुलिस के अनुसार पूर्व में दर्ज एनडीपीएस प्रकरण की विवेचना के दौरान कुछ महत्वपूर्ण तकनीकी सूचनाएं प्राप्त हुई थीं। इसी आधार पर 11-12 जून की दरमियानी रात थाना प्रभारी निरीक्षक जितेन्द्र सोनी के नेतृत्व में टीम ने थाना क्षेत्र में निगरानी बढ़ाई। रात्रि लगभग 2.30 से 3 बजे के बीच टाटा ट्रक क्रमांक आरजे-14-जी-9078 को रोककर जांच की गई। तलाशी के दौरान ट्रक से 62 पैकेटों में छिपाकर रखा गया 1941 किलो 110 ग्राम गांजा बरामद हुआ। मौके से सहारनपुर निवासी लोकेश शर्मा (46 वर्ष) और मुजफ्फरनगर निवासी आमिष अंसारी (23 वर्ष) को गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपियों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।

सबसे बड़ा सवालः इतनी बड़ी खेप रास्ते में कहां-कहां से गुजरी?

पुलिस का दावा है कि गांजा उड़ीसा से उत्तर प्रदेश ले जाया जा रहा था। यदि यह तथ्य सही है तो लगभग दो हजार किलो गांजा से भरा ट्रक कई जिलों और सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय कर बसंतपुर तक पहुंच गया।

ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है...

- क्या रास्ते में कहीं भी प्रभावी जांच नहीं हुई?
- विभिन्न राज्यों की सीमाओं पर स्थापित चेक पोस्ट क्या कर रहे थे?
- क्या तस्करों ने सुरक्षा तंत्र की कमजोरियों का फायदा उठाया?
- या फिर तस्करी नेटवर्क इतना संगठित हो चुका है कि वह लगातार जांच एजेंसियों को चुनौती दे रहा है?

विशेषज्ञों का मानना है कि इतनी बड़ी मात्रा में मादक पदार्थों का परिवहन किसी एक या दो व्यक्तियों का काम नहीं हो सकता। इसके पीछे एक संगठित अंतरराज्यीय नेटवर्क सक्रिय होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।

छह महीने में दूसरी बड़ी बरामदगी : यह पहला मामला नहीं है जब बसंतपुर पुलिस ने इतनी बड़ी कार्रवाई की हो। 29 दिसंबर 2025 को भी थाना बसंतपुर पुलिस ने एक टाटा ट्रक से 1198.460 किलोग्राम गांजा बरामद किया था। उस समय गांजा को नारियल भूसी के भीतर छिपाकर उड़ीसा से राजस्थान ले जाया जा रहा था। उस मामले में भी दो आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी। लगातार दूसरी बार इतनी बड़ी मात्रा में गांजा पकड़े जाने से यह संकेत मिलता है कि उत्तर प्रदेश-छत्तीसगढ़ सीमा क्षेत्र तस्करों के लिए महत्वपूर्ण ट्रांजिट कॉरिडोर के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है।

क्या केवल चालक और सहचालक तक सीमित रह जाएगी जांच?

एनडीपीएस के अधिकांश मामलों में अक्सर वाहन चालक और परिवहन से जुड़े लोग गिरफ्त में आ जाते हैं, लेकिन असली सरगना,फाइनेंसर और सप्लाई चेन संचालक कानून की पहुंच से दूर रह जाते हैं।

इस मामले में भी कुछ अहम प्रश्न हैं...

- गांजा उपलब्ध कराने वाला गिरोह कौन है?
- वास्तविक खरीदार कौन था?
- परिवहन की पूरी व्यवस्था किसने की?
- करोड़ों रुपए की खेप के पीछे फंडिंग किसकी थी?
- क्या इस मामले का संबंध दिसंबर 2025 में पकड़ी गई खेप से है?
- क्या दोनों मामलों में कोई समान नेटवर्क काम कर रहा था?

इन सवालों के जवाब जांच के बाद ही सामने आ सकेंगे।

नशे के कारोबार पर चिंता बढ़ी : सरगुजा संभाग और सीमावर्ती क्षेत्रों में पिछले कुछ वर्षों में मादक पदार्थों की तस्करी के मामले लगातार सामने आए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि तस्करी नेटवर्क की जड़ तक नहीं पहुंचा गया तो केवल खेप पकड़ने से समस्या का स्थायी समाधान संभव नहीं होगा। युवाओं तक नशे की पहुंच समाज और कानून व्यवस्था दोनों के लिए गंभीर चुनौती बनती जा रही है।

पुलिस की सफलता,लेकिन व्यवस्था के लिए चेतावनी भी : पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा दीपक कुमार झा और पुलिस अधीक्षक बलरामपुर वैभव बैंकर के निर्देशन में हुई यह कार्रवाई निस्संदेह बड़ी सफलता मानी जा रही है। तकनीकी निगरानी और पुलिस टीम की सतर्कता से करोड़ों रुपए का मादक पदार्थ बाजार तक पहुंचने से पहले पकड़ लिया गया। लेकिन यह घटना एक चेतावनी भी है कि नशे का कारोबार करने वाले नेटवर्क अभी भी सक्रिय हैं और लंबी दूरी तक अवैध खेप पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। जनहित का सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि 10 करोड़ रुपए का गांजा तो पकड़ लिया गया,लेकिन क्या जांच उन लोगों तक भी पहुंचेगी जो पर्दे के पीछे बैठकर इस पूरे कारोबार का संचालन कर रहे हैं? यदि ऐसा हुआ, तभी इस कार्रवाई को तस्करी नेटवर्क पर वास्तविक और निर्णायक प्रहार माना जाएगा।

जनरल परेड में अनुशासन और दक्षता पर जोर,डीआईजी-एसएसपी ने ली सलामी

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,12 जून 2026 (घटती-घटना)।

रक्षित केंद्र अंबिकापुर में शुक्रवार को आयोजित जनरल परेड में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के अनुशासन, दक्षता एवं पेशेवर कार्यशैली पर विशेष जोर दिया गया। जनरल परेड की सलामी डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा राजेश कुमार अग्रवाल ने ली तथा परेड का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। परेड निरीक्षण के दौरान डीआईजी एवं एसएसपी ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों के टर्नआउट,वेशभूषा और अनुशासन का बारीकी से अवलोकन किया। बेहतर वेशभूषा एवं उत्कृष्ट प्रस्तुति देने वाले पुलिसकर्मियों को पुरस्कृत कर प्रोत्साहित किया गया। इस दौरान पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों की विभिन्न टोलियां बनाकर परेड कराई गई तथा उन्हें सेवा के दौरान अनुशासन और कार्यकुशलता बनाए रखने के निर्देश दिए गए। परेड में पुलिस बैंड टीम की प्रस्तुति का भी निरीक्षण किया गया। डीआईजी एवं एसएसपी ने बैंड दल की तैयारियों की सराहना करते हुए आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया। परेड के पश्चात उन्होंने वाहन शाखा का निरीक्षण कर सभी शासकीय वाहनों की स्थिति की समीक्षा की। वाहनों के नियमित रखरखाव, समय-समय पर मरम्मत तथा लॉग बुक को अद्यतन रखने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा पुलिस लाइन स्थित शस्त्रागार एवं स्टोर शाखा का निरीक्षण करते हुए शस्त्रों और गोला-बारूद के सुरक्षित रखरखाव तथा अभिलेखों के सुव्यवस्थित संधारण पर विशेष ध्यान देने को कहा। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधिकारियों एवं जवानों के कल्याण के लिए संचालित पुलिस कल्याण कैंटीन और पुलिस बैंक की सुविधाओं का अधिक से अधिक लाभ लेने के लिए भी कर्मचारियों को प्रेरित किया गया।

बस स्टैंड से 16 लोगों का रेस्क्यू,मानव तस्करी की आशंका

झारखंड से कर्नाटक ले जाए जा रहे थे युवक-युवतियां,कई नाबालिग भी शामिल

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,12 जून 2026 (घटती-घटना)।

मानव तस्करी की आशंका पर महिला एवं बाल विकास विभाग की चाइल्ड लाइन टीम ने गुरुवार रात अंबिकापुर स्थित अंतरराज्यीय प्रतीक्षा बस स्टैंड में कार्रवाई करते हुए एक बस से 16 लोगों को रेस्क्यू किया। बस में कुल 20 लोग सवार थे,जिनमें कई नाबालिग लड़के और लड़कियां भी शामिल थे। सभी से पूछताछ और काउंसिलिंग की जा रही है। जानकारी के अनुसार जिला बाल संरक्षण इकाई और सामाजिक संगठन एमएसवीपी को सूचना मिली थी कि बड़ी संख्या में नाबालिग बालक-बालिकाओं तथा युवाओं को रोजगार दिलाने के नाम पर दूसरे राज्य ले जाया जा रहा है। सूचना के आधार पर टीम ने पुलिस की मदद से झारखंड से आई रॉयल बस की जांच की। पूछताछ में पता चला कि बस में सवार सभी लोग झारखंड के भंडरिया क्षेत्र के रहने वाले हैं। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार उन्हें कर्नाटक में विभिन्न कंपनियों में काम दिलाने और अधिक वेतन का झांसा देकर ले जाया जा रहा था। मानव तस्करी की आशंका को देखते हुए टीम ने सभी को बस से उतारकर सुरक्षित रेस्क्यू किया।

काउंसिलिंग के बाद होगी स्थिति स्पष्ट : रेस्क्यू किए गए लोगों को संरक्षण में लेकर उनकी काउंसिलिंग कराई जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि काउंसिलिंग और पूछताछ के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि मामला रोजगार के लिए पलायन का है या इसके पीछे मानव तस्करी का कोई संगठित नेटवर्क सक्रिय है। महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी जे.एस. प्रधान ने बताया कि सभी लोगों की काउंसिलिंग की जा रही है। पूरी जानकारी जुटाने के बाद ही मामले की वास्तविक स्थिति सामने आएगी। फिलहाल पुलिस और संबंधित विभाग सभी पहलुओं की जांच में जुटे हुए हैं।

मानव तस्करी गिरोह पर संदेह : प्रारंभिक जांच में जिस तरीके से युवाओं और नाबालिगों को दूसरे राज्य ले जाया जा रहा था, उसे देखते हुए मानव तस्करी की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। पुलिस अब यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि इन लोगों को कर्नाटक भेजने के पीछे कौन लोग सक्रिय थे और क्या इसके पीछे कोई संगठित गिरोह काम कर रहा है।

मवेशी तस्करों के मंसूबों पर पुलिस का प्रहार,12 मवेशी मुक्त,एक गिरफ्तार

-संवाददाता-
राजपुर,12 जून 2026 (घटती-घटना)।

बलरामपुर जिले की राजपुर थाना पुलिस ने मवेशी तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 12 मवेशियों को मुक्त कराया है। पुलिस ने तस्करी में प्रयुक्त एक पिकअप वाहन और एक ब्रेजा कार जब्त करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है,जबकि उसके चार साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 11 जून की रात गश्त के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि सफेद रंग की पिकअप वाहन क्रमांक पी-65 क्यूटी-1375 में मवेशियों को ठूंस-ठूंसकर बांधकर गोपालपुर कब्रिस्तान के पास से ले जाया जा रहा है। सूचना पर थाना प्रभारी भारद्वाज सिंह के निर्देशन में पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर संदिग्ध वाहन को रोककर जांच की। पूछताछ में चालक ने अपना नाम अशोक गिरी (50 वर्ष),निवासी डेरी कला,थाना बबुरी,जिला चंदौली (उत्तर प्रदेश) बताया। प्रारंभिक पूछताछ में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर कड़ाई से पूछताछ की गई। आरोपी ने बताया कि वह ग्राम फुली डुमर निवासी सलमान के कहने पर वाहन लेकर गोपालपुर पहुंचा था। वहां पहले से मौजूद कार क्रमांक पी-64 एआर-3563 में सवार कुछ लोगों की मदद से मवेशियों को पिकअप में लादकर परिवहन किया जा रहा था। पुलिस के पहुंचते ही आरोपी के चार साथी मौके से फरार हो गए। तलाशी के दौरान पिकअप वाहन में छह मवेशी रस्सियों से बांधकर अमानवीय तरीके से भरे हुए मिले, जबकि छह अन्य मवेशी घटनास्थल पर रस्सियों से बंधे पाए गए। पुलिस ने सभी 12 मवेशियों को मुक्त कर सुरक्षित कब्जे में लिया तथा दोनों वाहनों को जब्त कर थाना लाया। राजपुर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4, 6 एवं 10, पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11 तथा बीएनएस की धारा 3(5) के तहत मामला दर्ज कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है,वहीं फरार आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। पुलिस का कहना है कि जिले में मवेशी तस्करी के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और ऐसे मामलों में संलिप्त लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

शासकीय भूमि पर कब्जा और फर्जी शिकायत का आरोप ग्रामीणों ने आईजी व कलेक्टर से की कार्रवाई की मांग

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,12 जून 2026 (घटती-घटना)।

सरगुजा जिले के धौरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम अमड़ी के ग्रामीणों ने स्वास्थ्य विभाग के निलंबित कर्मचारियों पर शासकीय भूमि पर कब्जा करने,ग्रामीणों के फर्जी हस्ताक्षर कर मुख्यमंत्री को शिकायत भेजने तथा अन्य अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों ने सरगुजा रेंज के आईजी और कलेक्टर को लिखित शिकायत सौंपकर निष्पक्ष जांच एवं कार्रवाई की मांग की है। कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम अमड़ी निवासी स्वयम्बर सिंह और उनकी पत्नी प्रियंका सिंह स्वास्थ्य केंद्र धौरपुर में एम पी एच डब्ल्यू पद पर पदस्थ हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि स्वयम्बर सिंह के पिता कुंवर साय गांव में झाड़-फूंक के माध्यम से अंधविश्वास फैलाने का कार्य करते हैं। साथ ही प्रियंका सिंह का फर्जी निवास प्रमाण पत्र बनवाकर नौकरी प्राप्त करने का भी आरोप लगाया गया है। ग्रामीणों ने शिकायत में कहा है कि ग्राम अमड़ी स्थित स्कूल मद की लगभग 8 डिसमिल शासकीय भूमि पर कब्जा कर मकान निर्माण किया गया है। इसके अलावा गांव की अशिक्षित वृद्ध महिला कविलासो की संयुक्त खाते वाली उपजाऊ भूमि को बिना उचित मूल्य दिए कथित रूप से फर्जी और कूटरचित दस्तावेजों के माध्यम से अपने नाम करवाने का आरोप भी लगाया गया है। शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि शासकीय सेवा में रहते हुए दोनों द्वारा निजी नेटवर्क मार्केटिंग और हर्बल लाइफ वेलनेस कोचिंग का प्रचार-प्रसार किया जा रहा था। ग्रामीणों के अनुसार इस संबंध में हुई शिकायत की जांच के बाद स्वास्थ्य विभाग ने दोनों को निलंबित कर दिया था। वहीं शासकीय भूमि पर किए गए निर्माण को हटाने के लिए तहसीलदार लुंड्रा द्वारा बेदखली का आदेश भी जारी किया गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि निलंबन और बेदखली की कार्रवाई के बाद स्वयम्बर सिंह और प्रियंका सिंह ने गांव के लोगों तथा लंबे समय से उपसरपंच रहे सूरज प्रसाद गुप्ता और उनकी पत्नी के खिलाफ रंजिशवश झूठी एवं मनगढ़ंत शिकायत मुख्यमंत्री को भेजी। शिकायत में ग्रामवासियों के फर्जी हस्ताक्षर किए जाने का भी आरोप लगाया गया है। ग्रामीणों ने बताया कि इस संबंध में 7 जून को धौरपुर थाने में शिकायत दी गई थी, लेकिन अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है। इसके बाद उन्होंने कलेक्टर और आईजी से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करने की मांग की है। ज्ञापन सौंपने वालों में लक्ष्मी प्रसाद कश्यप, दिनेश पावले, राजन सिंह, रामनाथराम,हीरासाय,गुड्डू रामकुमार,अरविंद बेक,भोला, कृष्णा यादव,दशरथ,रामकिशुन, बसंतयादव,दिलीप,फुलासो, बिगन,नानसाय सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल रहे।

आरपीए कृषि फार्म करजी में अनियमितता मिलने पर 56 बोरी यूरिया के विक्रय पर लगा प्रतिबंध

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,12 जून 2026 (घटती-घटना)।

जिला कलेक्टर अजीत वसंत के निर्देशन तथा उप संचालक कृषि श्री पीतांबर सिंह दीवान के मार्गदर्शन में कृषि विभाग द्वारा जिले में खाद एवं उर्वरकों की कालाबाजारी पर रोक लगाने तथा वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए लगातार औचक निरीक्षण एवं जांच की कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में 11 जून 2026 को विकासखंड अंबिकापुर अंतर्गत आरपीए कृषि फार्म, करजी में ब्लॉक स्तरीय जांच दल द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कृषि फार्म में उपलब्ध उर्वरकों के भौतिक स्टॉक तथा पी.ओ.एस. मशीन में दर्ज स्टॉक रिकॉर्ड का मिलान किया गया, जिसमें असमानता एवं अन्य अनियमित ताएं पाई गईं। जांच के दौरान नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होने पर कृषि विभाग द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए फार्म में उपलब्ध 56 बोरी यूरिया के विक्रय पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है। विभाग द्वारा मामले की विस्तृत जांच भी की जा रही है। इस कार्रवाई के दौरान वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी एवं उर्वरक निरीक्षक श्री जे.आलम,ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी श्री सीताराम भगत,श्री विजय गुप्ता तथा कृषि तकनीकी विशेषज्ञ श्री विनोद पैंकरा उपस्थित रहे। उप संचालक कृषि श्री पीतांबर सिंह दीवान ने कहा है कि खाद एवं उर्वरकों के भंडारण, वितरण और विक्रय में अनियमितता पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों एवं संस्थानों के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल की बिक्री की सीमा भी निर्धारित

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,12 जून 2026 (घटती-घटना)।

भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 11 जून 2026 को ईंधन वितरण को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार औद्योगिक, वाणिज्यिक और संस्थागत उपभोक्ताओं को खुदरा पेट्रोल पंपों से पेट्रोल या डीजल खरीदने अथवा मंगाने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ऐसे उपभोक्ताओं को अपनी आवश्यकता की पूर्ति अधिकृत उपभोक्ता

पंपों के माध्यम से ही करनी होगी। मंत्रालय ने एक ग्राहक या वाहन को एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल की बिक्री की सीमा भी निर्धारित की है। साथ ही खरीदे गए डीजल के पुनर्विक्रय पर भी रोक लगाई गई है। तेल विपणन कंपनियों और पेट्रोल पंप डीलरों को इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने कहा गया है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को भी निर्देशित किया है कि जमाखोरी, कालाबाजारी, अनधिकृत भंडारण और ईंधन वितरण में होने वाली अन्य अनियमितताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इसके लिए संबंधित विभागों को निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। शहर में ईंधन की सीमित बिक्री और बढ़ती मांग के कारण वाहन चालकों में चिंता का माहौल है। हालांकि प्रशासन और तेल कंपनियों की ओर से स्थिति सामान्य बनाए रखने के प्रयास किए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में आपूर्ति की स्थिति स्पष्ट होने के बाद ही राहत मिलने की उम्मीद है।

इधर शहर के कई पेट्रोल पंप ड्राई : शहर में पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता को लेकर संकट के संकेत दिखाई देने लगे हैं। कई पेट्रोल पंपों पर ईंधन की कमी की स्थिति बन गई है, जबकि कुछ पंप संचालकों ने बिक्री पर सीमा निर्धारित कर दी है। इससे वाहन चालकों की परेशानी बढ़ गई है और लोग आवश्यकतानुसार ईंधन नहीं भरवा पा रहे हैं। जानकारी के अनुसार शहर के कुछ पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल का स्टॉक सीमित होने के कारण बाइक चालकों को 200 रुपए से अधिक का पेट्रोल नहीं दिया जा रहा है। वहीं चार पहिया वाहनों के लिए भी 400 रुपए तक ईंधन देने की सीमा तय की गई है। स्थिति को देखते हुए कई वाहन चालक एक पंप से दूसरे पंप तक भटकते नजर आए।

CMYK

वन विभाग की नाक के नीचे रेत का साम्राज्य? मेरो-आमाडांड-मुकुंदपुर में अवैध खनन के आरोपों से उठे बड़े सवाल....

रेत माफिया मालामाल,गरीब हितग्राही बेहाल-क्या यही है खनन नियंत्रण की हकीकत?

-राजेंद्र शर्मा-

खड़गवां/चिरमिरी 12 जून 2026 (घटती-घटना)।

एक तरफ शासन अवैध खनन पर सख्ती के दावे कर रहा है,दूसरी तरफ चिरमिरी वन परिक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मेरो,आमाडांड और मुकुंदपुर क्षेत्र में अवैध रेत खनन और परिवहन को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं,स्थानीय ग्रामीणों और सूत्रों के आरोपों ने वन विभाग की कार्यप्रणाली को कठघरे में ला खड़ा किया है, आरोप हैं कि क्षेत्र में महीनों से खुलेआम रेत का उत्खनन और परिवहन हो रहा है,लेकिन जिम्मेदार विभाग की ओर से प्रभावी कार्रवाई दिखाई नहीं दे रही, क्षेत्र में चर्चा का विषय यह है कि आखिर वह कौन-सी अदृश्य शक्ति है जो रेत से भरे वाहनों को निर्भय होकर सड़कों पर दौड़ने की अनुमति दे रही है? और यदि सब कुछ नियमों के अनुसार हो रहा है तो फिर ग्रामीणों और स्थानीय लोगों के बीच इतनी नाराजगी क्यों है? बता दे की चिरमिरी वन परिक्षेत्र में अवैध रेत खनन और परिवहन को लेकर उठे सवाल अब केवल अफवाह या स्थानीय चर्चा तक सीमित नहीं रह गए हैं,ग्रामीणों की शिकायतें, लगातार लग रहे आरोप और विभाग की चुप्पी इस मामले को गंभीर बना रहे हैं,आरोप सही हैं या गलत, इसका फैसला निष्पक्ष जांच ही कर सकती है, लेकिन जब तक जांच नहीं होती, तब तक सवाल उठते रहेंगे और लोगों के मन में यह शंका बनी रहेगी कि आखिर रेत के इस खेल में कौन-कौन शामिल है और किसके संरक्षण में यह कारोबार फल-फूल रहा है।

रेत का कारोबार या संरक्षण का खेल?-स्थानीय सूत्रों का दावा है कि मेरो, आमाडांड और मुकुंदपुर क्षेत्र में लंबे समय से रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा है,आरोप है कि नदी-नालों से रेत निकालकर प्रतिदिन बड़ी संख्या में ट्रैक्टर और अन्य वाहन चिरमिरी क्षेत्र की ओर भेजे जा रहे हैं, सबसे गंभीर आरोप यह है कि यह पूरा कारोबार विभागीय निगरानी से बाहर नहीं बल्कि कथित रूप से उसकी जानकारी में चल रहा है,क्षेत्र में यह चर्चा भी जोरों पर है कि अवैध खनन और परिवहन में लगे कुछ लोगों तथा विभाग के कुछ जिम्मेदार अधिकारियों के बीच सांठगांठ होने के कारण कार्रवाई नहीं हो रही,हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है,लेकिन लगातार उठ रहे सवालों ने जांच की आवश्यकता को और मजबूत कर दिया है।

गरीबों पर डंडा,माफियाओं पर चुप्पी?-ग्रामीणों का आरोप है कि प्रधानमंत्री आवास योजना और अन्य निजी निर्माण कार्यों के लिए गिट्टी या निर्माण सामग्री ले जाने वाले छोटे वाहन चालकों को रोककर पूछताछ की जाती है,कई लोगों ने कथित रूप से अनावश्यक परेशान किए जाने की शिकायत भी की है, यहीं से विवाद और गहरा हो जाता है,ग्रामीण पूछ रहे हैं कि यदि कुछ ट्रॉली गिट्टी लेकर जाने वाले लोगों पर इतनी सख्ती दिखाई जाती है तो फिर प्रतिदिन निकल रहे कथित रेत वाहनों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? यह सवाल अब गांवों की चौपालों से निकलकर प्रशासनिक व्यवस्था तक पहुंचने लगा है।

पर्यावरण पर भी मंडरा रहा खतरा-रेत खनन का मुद्दा केवल राजस्व या कानून-व्यवस्था का विषय नहीं है, अनियंत्रित और अवैध खनन का सीधा असर पर्यावरण पर पड़ता है, विशेषज्ञों के अनुसार अत्यधिक रेत निकासी से नदी और नालों की प्राकृतिक संरचना प्रभावित होती है, जल स्तर पर असर पड़ता है, कटाव बढ़ता है और भविष्य में जल संकट जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं, इसीलिए खनन को नियमों और वैज्ञानिक मानकों के तहत नियंत्रित किया जाता है, लेकिन यदि आरोप सही हैं और अवैध खनन लंबे समय से जारी है, तो पर्यावरणीय नुकसान की भी जांच जरूरी होगी।

ग्रामीणों में बढ़ रहा आक्रोश-मेरो, आमाडांड और मुकुंदपुर क्षेत्र के लोगों का कहना है कि वे लंबे समय से इस विषय को उठा रहे हैं,लेकिन अभी तक ठोस कार्रवाई दिखाई नहीं दी,ग्रामीणों का मानना है कि यदि प्रशासन वास्तव में गंभीर है तो पूरे मामले की स्वतंत्र जांच कराई जानी चाहिए, साथ ही यह भी देखा जाना चाहिए कि कहीं विभागीय स्तर पर लापरवाही या मिलीभगत तो नहीं हुई, लोगों का कहना है कि यदि छोटे लोगों पर कार्रवाई हो सकती है तो बड़े स्तर पर हो रहे कथित अवैध कारोबार पर भी समान रूप से सख्ती होनी चाहिए।

उठ रहे हैं ये बड़े सवाल-अब पूरे मामले में कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर क्षेत्र की जनता जानना चाहती है क्या मेरो,आमाडांड और मुकुंदपुर क्षेत्र में अवैध रेत खनन वास्तव में हो रहा है? यदि हो रहा है तो अब तक कितनी कार्रवाई की गई? वन परिक्षेत्र कार्यालय के सामने से गुजरने वाले वाहनों की जांच क्यों नहीं हुई? गिट्टी और निर्माण सामग्री ले जाने वाले गरीब हितग्राहियों पर सख्ती और कथित रेत कारोबारियों पर नरमी क्यों दिखाई जा रही है? क्या विभागीय अधिकारियों की भूमिका की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी? और सबसे महत्वपूर्ण–क्या शासन इस पूरे मामले को गंभीरता से लेकर जनता के सामने सच्चाई रखेगा?

वन परिक्षेत्र कार्यालय के सामने से गुजरते वाहन और उठते सवाल...

क्षेत्रवासियों का कहना है कि जिन मार्गों से रेत का परिवहन हो रहा है,वे कोई गुप्त रास्ते नहीं हैं, कई वाहन ऐसे मार्गों से गुजरते हैं जहां विभागीय अमला नियमित रूप से मौजूद रहता है,ऐसे में लोगों का सवाल है कि क्या विभाग को यह गतिविधियां दिखाई नहीं देतीं? यदि दिखाई देती हैं तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? और यदि दिखाई नहीं देतीं तो फिर निगरानी व्यवस्था कितनी प्रभावी है? इन सवालों का जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है।

वसूली की चर्चाओं ने बढ़ाई गंभीरता...

क्षेत्र में यह चर्चा भी जोर पकड़ रही है कि अवैध खनन और परिवहन से जुड़े कुछ वाहन मालिकों से कथित रूप से रकम वसूली गई है,हालांकि इन दावों के समर्थन में अभी तक कोई आधिकारिक दस्तावेज सार्वजनिक नहीं हुआ है,लेकिन लगातार फैल रही चर्चाओं ने पूरे मामले को और संवेदनशील बना दिया है,यदि इन आरोपों में जरा भी सच्चाई निकलती है तो मामला केवल अवैध खनन का नहीं रहेगा, बल्कि संरक्षण और भ्रष्टाचार जैसे गंभीर प्रश्न भी खड़े होंगे,इसी वजह से ग्रामीण और सामाजिक कार्यकर्ता निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं।

वन विभाग का पक्ष...

आप खबर प्रकाशित कर दीजिए...

अवैध रेत उत्खनन और परिवहन के संबंध में पूछे जाने पर चिरमिरी वन परिक्षेत्र के रेंजर टेकाम सिंह ठाकुर ने कहा कि विभाग को यदि ऐसे मामलों की जानकारी मिलती है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाती है,उन्होंने कहा, आप खबर प्रकाशित कर दीजिए,उसके बाद कार्रवाई की जाएगी,रेंजर का कहना है कि शिकायतों और तथ्यों के आधार पर जांच कर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

देर रात अस्पताल पहुंचे विधायक...व्यवस्थाओं का लिया जायजा

मरीजों से बातचीत कर जानी स्वास्थ्य सुविधाओं की हकीकत,लापरवाही पर जताई सख्ती

-संवाददाता-

सीतापुर,12 जून 2026 (घटती-घटना)।

सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो ने गुरुवार देर रात 100 बिस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा मरीजों और उनके परिजनों से सीधे बातचीत कर स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली। विधायक ने अस्पताल के विभिन्न वार्डों का भ्रमण कर साफ-सफाई, दवाओं की उपलब्धता और कर्मचारियों की उपस्थिति की जांच की। उन्होंने भर्ती मरीजों से उपचार व्यवस्था,डॉक्टरों की उपलब्धता

तथा मिलने वाली सुविधाओं के संबंध में जानकारी ली। इस दौरान कुछ व्यवस्थाओं में सुधार की आवश्यकता महसूस होने पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। विधायक टोप्पो ने उपचार में किसी भी प्रकार की लापरवाही और अनावश्यक देरी पर नाराजगी जताते हुए अस्पताल प्रबंधन को सख्त चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि मरीजों के इलाज में किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही या शिकायत मिली तो संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल स्टाफ को समय पर ड्यूटी करने, मरीजों के प्रति संवेदनशील व्यवहार रखने और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अस्पताल आने वाले प्रत्येक मरीज को समय पर उपचार और आवश्यक सुविधाएं मिलनी चाहिए। विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की मंशा के अनुरूप आम जनता को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की प्राथमिक जिम्मेदारी है।

सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और इसमें किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। औचक निरीक्षण से अस्पताल प्रबंधन और कर्मचारियों में हड़कंप की स्थिति रही। विधायक ने भविष्य में भी इसी तरह निरीक्षण जारी रखने की बात कही।

ओएलएक्स पर विज्ञापन डालना पड़ा महंगा,छात्रा से 29 हजार की ठगी

-संवाददाता-

अम्बिकापुर,12 जून 2026 (घटती-घटना)।

पुराना सोफा बेचने के लिए ओएलएक्स में विज्ञापन डालनेवाली कॉलेज की छात्रा 29 हजार रुपये ठगी का शिकार हो गई। रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, और अग्रिम जांच, कार्रवाई कर रही है। कोतवाली थाना अंतर्गत चोपड़ापारा में रहने वाली कॉलेज की छात्रा ने पुलिस को बताया है कि,घर के पुराना सोफा को बेचने के लिए वह ओएलएक्स में विज्ञापन डाली थी। 9 जून को शाम करीब 7.30 बजे उसके मोबाइल में कॉल आया,जिसने अपना नाम राजेश बताया और सोफा खरीदने के लिए 15 हजार रुपये में सौदा तय करके आर्डर किया। इसके बाद उक्त व्यक्ति विश्वास में लेने के लिये ऑनलाइन फोन पे के माध्यम से कुछ राशि का ट्रांजेक्शन किया। इसके बाद अपना क्युआर कोड भेजकर स्केन करने कहा और धोखाधड़ी करके 29,990 रुपये ट्रांजेक्शन कर लिया,इस प्रकार दो बार में 29,990 रुपये की बैंक खाते से कटौती कर ली गई। रिपोर्ट पर कोतवाली थाना पुलिस ने धारा 318(4) बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है।

स्वदेशी अर्थव्यवस्था पर मंथन करेगा अंबिकापुर 13-14 जून को होगा प्रांतीय विचार वर्ग...

-संवाददाता-

अम्बिकापुर,12 जून 2026 (घटती-घटना)।

वैश्विक आर्थिक चुनौतियों और आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा के बीच स्वदेशी आधारित आर्थिक मॉडल पर मंथन के लिए स्वदेशी जागरण मंच का दो दिवसीय प्रांतीय विचार वर्ग 13 एवं 14 जून को अंबिकापुर के माखन विहार में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में प्रदेशभर से लगभग 150 प्रतिनिधि एवं कार्यकर्ता शामिल होंगे। स्वदेशी जागरण मंच सरगुजा के संभाग संयोजक राजकिशोर चौधरी ने बताया कि विचार वर्ग में देश के प्रख्यात अर्थशास्त्री एवं स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय सह-संयोजक अश्वनी महाजन तथा क्षेत्र प्रमुख प्रतिनिधि सुधीर दाते का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। दोनों विषय विशेषज्ञ वर्तमान वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों, भारतीय अर्थव्यवस्था की चुनौतियों तथा स्वदेशी मॉडल की संभावनाओं पर अपने विचार रखेंगे। दो दिवसीय आयोजन में 'अर्थव्यवस्था में स्वदेशी' विषय को केंद्र में रखते हुए विभिन्न सत्र आयोजित किए जाएंगे। इनमें आर्थिक आत्मनिर्भरता, स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा, स्वदेशी उद्योगों के संरक्षण और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के बीच भारतीय आर्थिक मॉडल की प्रासंगिकता जैसे विषयों पर चर्चा होगी। कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण आकर्षण स्थानीय व्यापारियों एवं उद्योग जगत से जुड़े प्रबुद्धजनों के साथ संवाद सत्र रहेगा। इस दौरान

क्षेत्रीय आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने जैसे मुद्दों पर विचार-विमर्श किया जाएगा। विचार वर्ग के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में अंबिकापुर विधायक एवं प्रदेश के कैबिनेट मंत्री राजेश अग्रवाल उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम में स्वदेशी जागरण मंच के प्रांत संयोजक जगदीश पटेल, प्रांत संपर्क प्रमुख शुभव्रत चाकी सहित प्रदेश एवं संभाग स्तर के पदाधिकारी भी शामिल होंगे।

कार्यक्रम का शुभारंभ 13 जून को प्रातः 10:30 बजे होगा तथा विभिन्न विषयगत सत्रों के बाद इसका समापन 14 जून को सायंकाल किया जाएगा। आयोजकों के अनुसार यह विचार वर्ग प्रदेश में स्वदेशी चिंतन को मजबूत करने तथा आर्थिक विषयों पर व्यापक संवाद का महत्वपूर्ण मंच बनेगा।

केन्द्रीय जेल अंबिकापुर के 100 मीटर दायरे को घोषित किया गया रेड जोन,ड्रोन एवं हवाई उपकरणों के उपयोग पर प्रतिबंध

-संवाददाता-

अम्बिकापुर,12 जून 2026 (घटती-घटना)।

केन्द्रीय जेल अंबिकापुर की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने तथा जेल परिसर में प्रतिबंधित सामग्री की संभावित आपूर्ति को रोकने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अजीत वसंत ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। जेल अधीक्षक,केन्द्रीय जेल अंबिकापुर तथा मुख्यालय जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं,रायपुर से प्राप्त निर्देशों के अनुक्रम में यह आदेश जारी किया गया है। केन्द्रीय जेल अंबिकापुर चारों ओर से आवासीय बस्तियों से घिरा हुआ है, जिससे असामाजिक तत्वों द्वारा ड्रोन अथवा अन्य हवाई माध्यमों से जेल परिसर में प्रतिबंधित सामग्री पहुंचाए जाने की आशंका बनी रहती है। जारी आदेश के अनुसार केन्द्रीय जेल अंबिकापुर की मुख्य दीवार के बाहर 100 मीटर की परिधि को रेड जोन एवं नो-फ्लाई जोन घोषित किया गया है। इस क्षेत्र में ड्रोन, गुब्बारे तथा किसी भी प्रकार के विमानन उपकरणों के उड़ान संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके

अतिरिक्त जेल की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ड्रोन, गुब्बारे अथवा अन्य हवाई उपकरणों के माध्यम से किसी भी प्रकार की हवाई फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 तथा अन्य प्रासंगिक विधिक प्रावधानों के अंतर्गत दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे

आउटसोर्सिंग कार्य हेतु ई-निविदा सूचना

क्र.संख्या (1) ई-निविदा संख्या:08- एसटी-टेंडर-2026, दिनांक: 08.06.2026. कार्य: "इंजीनियरिंग मशीनों और इंजीनियरिंग से जुड़े अन्य ब्लॉक कार्यों के लिए गैंग (मैनपावर) की आउटसोर्सिंग की व्यवस्था।" निविदा मूल्य: ₹4,28,64,953.95 (₹ चार करोड़ अट्ठाईस लाख चौंसठ हजार नौ सौ तिरपन रुपये और पचानवे पैसे मात्र)। अमानत राशि: ₹ 8,57,300/- (₹ आठ लाख सत्तावन हजार तीन सौ मात्र)।

निविदा जमा होने की तिथि: 30.06.2026 के 15.00 बजे तक।

उपरोक्त ई–निविदा सूचना की पूरी जानकारी वेबसाइट https://www.ireps.gov.in पर उपलब्ध है। उपरोक्त निविदा हेतु ई–टेन्डर के अलावा अन्य निविदा स्वीकार नही की जाएगी।

मंडल संकेत एवं दूरसंचार इंजी./सीपीआर/10/191 (मेन लाईन),बिलासपुर

South East Central Railway @secrail

R.O.No.MUM0947/26-27

न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय दण्डाधिकारी महोदय,अम्बिकापुर,सरगुजा

आ0क्र0...../2025-26

ईश्तहार

यह प्रमाणित किया जाता है कि, मै विजय शर्मा पिता स्व0 रामचन्द्र प्रसाद निवासी ग्राम सोनडीहा पो0 बरतीकलां थाना चंदौरा तह0 प्रतापपुर जिला सूरजपुर छ0ग0 का निवासी हूँ मेरी पुत्री आयषु शर्मा का नाम आधार कार्ड में कु0 आर्यशु से बदल कर नाम परिवर्तन कर आयषु शर्मा दर्ज करवाना चाहता हूँ। इस संबंध में इश्तेहार का प्रकाशन किया जाना आवश्यक हो गया है। अतः इश्तेहार का प्रकाशन किये जाने का आदेश देने की कृपा हो ।

अम्बिकापुर
दिनांक 12/06/2026

विजय कुमार शर्मा
आवेदक

अनधिकृत अनुपस्थिति एवं आदेशों की अवहेलना पर संविदा शिक्षक की सेवा समाप्त

-संवाददाता-

अम्बिकापुर,12 जून 2026 (घटती-घटना)।

जिला शिक्षा अधिकारी डॉ दिनेश झा द्वारा स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय (सेजेस) नर्मदापुर, विकासखण्ड मैनपाट में पदस्थ संविदा शिक्षक (कम्प्यूटर) श्रीमती आकांक्षा जायसवाल की संविदा सेवा समाप्त करने का आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश के अनुसार प्राचार्य, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय नर्मदापुर द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी में बताया गया कि श्रीमती आकांक्षा जायसवाल जुलाई 2023 से सितंबर 2023 तक अवैतनिक अवकाश पर तथा नवंबर 2023 से 25 जून 2024 तक प्रसूति अवकाश पर रहीं।

विवाहिता की मौत के बाद विवाद,पिता ने पति पर लगाया जबरन जहर खिलाने का आरोप

इलाज के दौरान निजी अस्पताल में तोड़ा दम, पुलिस ने दोनों पक्षों के बयान दर्ज कर शुरू की जांच

-संवाददाता-

अम्बिकापुर/पटना,12 जून 2026 (घटती-घटना)।

कोरिया जिले की एक विवाहिता की कीटनाशक सेवन से मौत हो गई। उसका इलाज अंबिकापुर के एक निजी अस्पताल में चल रहा था। मामले में मृतका के पिता ने दामाद पर मारपीट कर जबरन जहर खिलाने का आरोप लगाया है, जबकि पति का कहना है कि पत्नी ने विवाद के बाद स्वयं कीटनाशक का सेवन किया था। मेडिकल कॉलेज अस्पताल सहायता केंद्र पुलिस ने दोनों पक्षों के बयान दर्ज कर मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार कोरिया जिले के पटना थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम लेडुआ निवासी आरती साहू (25) की शादी वर्ष 2021 में दिनेश साहू से हुई थी। दंपती के दो बच्चे हैं। पति दिनेश साहू ने पुलिस को बताया कि 10 मई को किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था। विवाद के बाद आरती ने गुस्से में आकर कीटनाशक पी लिया। तबीयत बिगड़ने पर उसे तत्काल सूरजपुर जिला अस्पताल ले जाया गया,जहां से प्राथमिक उपचार के बाद अंबिकापुर रेफर कर दिया गया। इसके बाद उसे शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं मृतका के पिता हंश साहू ने घटना को लेकर अलग आरोप लगाए हैं।

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार अम्बिकापुर-2, जिला-सरगुजा,छ0ग0

रा.प्र.क्र./अ-6/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक मोहर लाल आ. स्व. जुगेश्वर व अन्य, जाति गोड़, निवासी ग्राम परसा, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ0ग0 द्वारा ग्राम परसा स्थित भूमि खसरा नंबर 338 / 2, 379/1, 452/2, 2165, 2183/1, 2185/1, 2186/1, 2187, 2203/2, 2220/2, 2221/2, 2361/2, 243/1 कुल रकबा 1.608 हे0 भूमि के राजस्व अभिलेखो में वर्तमान मृत खातेदार स्व0 जुगेश्वर का नाम विलोपित कराते हुए उनके विधिक वारिशों के नाम पर फौती दर्ज कराने बावत् आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

उक्त संबंध में किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो पेशी दिनांक 10/07/2026 को न्यायालय में स्वंय अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है । समय सीमा के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा ।

आज दिनांक 12/06/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी ।

सील — अतिरिक्त तहसीलदार अम्बिकापुर-2

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी भटगांव तहसील भैयाथान,जिला-सूरजपुर

ईश्तहार

रा.प्र.क्र...../ब-121/2026

आम जनता ग्राम भटगांव को सूचित किया जाता है कि आवेदक मोहरमनिया राजवाड़े आ0 सतन जाति रजवार निवासी ग्राम भटगांव तहसील भटगांव जिला सूरजपुर द्वारा अपने स्वयं का जन्म दिनांक 05/07/2001 को जन्म/मृत्यु होने पर आवेदक द्वारा अपने जन्म प्रमाण पत्र के पंजीयन बावत् शुल्क अदा कर चालान की प्रति, शपथ पत्र अनुपलब्धतां प्रमाण पत्र सहित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसमें कार्यवाही प्रारंभ कर दी गयी है।

जिस किसी हितबद्ध पक्षकार को कोई आक्षेप हो तो वह अपना आक्षेप दिनांक 19/06/2026 तक मेरे न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है। नियत तिथि के पश्चात् प्राप्त आक्षेप पर कोई विचार नहीं किया जावेगा एवं तदनुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

आज दिनांक 05/06/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से जारी किया गया ।

सील — कार्यपालिक दण्डाधिकारी भटगांव जिला-सूरजपुर

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी भटगांव तहसील भैयाथान,जिला-सूरजपुर

ईश्तहार

रा.प्र.क्र...../ब-121/2026

आम जनता ग्राम चुनगडी को सूचित किया जाता है कि आवेदक फुलबसिया पति स्व0 ननकू जाति गोड़ निवासी ग्राम चुनगडी तहसील भटगांव जिला सूरजपुर द्वारा अपने पति का मृत्यु दिनांक 11/06/2008 को जन्म/मृत्यु होने पर आवेदक द्वारा अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र के पंजीयन बावत् शुल्क अदा कर चालान की प्रति, शपथ पत्र अनुपलब्धतां प्रमाण पत्र सहित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसमें कार्यवाही प्रारंभ कर दी गयी है।

जिस किसी हितबद्ध पक्षकार को कोई आक्षेप हो तो वह अपना आक्षेप दिनांक 19/06/2026 तक मेरे न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है। नियत तिथि के पश्चात् प्राप्त आक्षेप पर कोई विचार नहीं किया जावेगा एवं तदनुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

आज दिनांक 09/06/2026 को मेरे हरताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से जारी किया गया ।

सील — कार्यपालिक दण्डाधिकारी भटगांव जिला-सूरजपुर

न्यायालय तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी भटगांव ,जिला-सूरजपुर

ईश्तहार

रा.प्र.क्र...../ब-121/2026

आम जनता ग्राम दुग्गा को सूचित किया जाता है कि आवेदक बुधू राजवाडे पिता आगरसाय राजवाड़े जाति रजवार निवासी ग्राम दुग्गा तहसील व थाना भटगांव जिला सूरजपुर छ0ग0 द्वारा आवेदक के पुत्र गौतम राजवाड़े का जन्म दिनांक 03/06/2006 को ग्राम दुग्गा मे घर मे जन्म होना बताकर जन्म प्रमाण पत्र के पंजीयन बावत मय आवेदन, शपथ पत्र, अनुपलब्धता प्रमाण पत्र, ग्राम पंचायत का पंचनामा, सहित स्थानीय रजिस्ट्रार (जन्म / मृत्यु) का रजिस्ट्रीकरण (मध्यप्रदेश) निगम 1969 के नियम 10 (13) के अन्तर्गत निर्देश देने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

उक्त जन्म प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध मे जिस किसी व्यक्ति या संस्था कोई आपत्ति हो तो दिनांक 19/06/2026 को समय 11.00 बजे इस न्यायालय मे अपना अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर आपत्ति दावा प्रस्तुत कर सकता है। नियत तिथि बाद प्राप्त आपत्ति / दावा पर कोई विचार नही किया जावेगा । तदनुसार कार्यवाही कर दी जावेगी ।

आज दिनांक 05/06/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

सील — कार्यपालिक दण्डाधिकारी भटगांव जिला-सूरजपुर

न्यायालय तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी भटगांव ,जिला-सूरजपुर

ईश्तहार

रा.प्र.क्र...../ब-121/2026

आम जनता ग्राम धरमपुर को सूचित किया जाता है कि आवेदक पतिराम पिता पियाराम जाति कवंर निवासी ग्राम धरमपुर तहसील भटगांव जिला सूरजपुर छ0ग0 द्वारा अपने स्वयं का जन्म दिनांक 30/09/1966 को ग्राम धरमपुर मे घर मे जन्म होना बताकर जन्म प्रमाण पत्र के पंजीयन बावत मय आवेदन, शपथ पत्र, अनुपलब्धता प्रमाण पत्र, ग्राम पंचायत का पंचनामा, सहित स्थानीय रजिस्ट्रार (जन्म / मृत्यु) का रजिस्ट्रीकरण (मध्यप्रदेश) निगम 1969 के नियम 10 (13) के अन्तर्गत निर्देश देने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

उक्त जन्म प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध मे जिस किसी व्यक्ति या संस्था कोई आपत्ति हो तो दिनांक 19/06/2026 को समय 11.00 बजे इस न्यायालय मे अपना अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर आपत्ति दावा प्रस्तुत कर सकता है। नियत तिथि बाद प्राप्त आपत्ति / दावा पर कोई विचार नही किया जावेगा । तदनुसार कार्यवाही कर दी जावेगी ।

आज दिनांक 05/06/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया ।

सील — कार्यपालिक दण्डाधिकारी भटगांव जिला-सूरजपुर

सुशासन तिहार का महाउत्सव, समस्याओं का वनवास

सोनहत में मंच चमके, जनता अंधेरे में!

-राजन पाण्डेय-

कोरिया,12 जून 2026 (घटती-घटना)।

सोनहत में एक बार फिर सुशासन तिहार का मेला लगा, मंच सजे, कुर्सियां लगीं,माइक गरजे, अधिकारी मुस्कुराए,नेताओं ने जनता को विकास का नया सपना दिखाया और सरकारी अमले ने उपलब्धियों की ऐसी लंबी सूची पढ़ी कि सुनने वालों को लगा मानो सोनहत अब सीधे स्मार्ट सिटी बनने की कतार में खड़ा हो गया हो।

मंच से बताया गया कि शासन जनता के द्वार पहुंच रहा है, समस्याओं का समाधान हो रहा है, विकास की गंगा बह रही है, सुशासन घर-घर दस्तक दे रहा है, लेकिन जैसे ही कार्यक्रम खत्म हुआ,मंच उखड़ा और अधिकारी वाहनों में बैठकर लौटे, वैसे ही सोनहत की जनता फिर उसी पुरानी हकीकत के सामने खड़ी दिखाई दी–अंधेरी सड़कें,बंद नेटवर्क,अधूरी बिजली,टूटी पुलिया, सूखे नल और दफ्तरों के चक्कर काटते आदिवासी, ऐसा लगने लगा है कि सोनहत में सुशासन अब समस्या समाधान का कार्यक्रम कम और सरकारी उपलब्धियों का सांस्कृतिक उत्सव ज्यादा बनता जा रहा है।

पानी के लिए त्राहि-त्राहि,नहरें दम तोड़ रहीं...

गर्मी की शुरुआत के साथ ही पेयजल संकट ने दस्तक दे दी है,कई गांवों में महिलाएं दूर-दूर से पानी लाने को मजबूर हैं,हैंडपंप जवाब दे रहे हैं,जल स्रोत सिकुड़ रहे हैं, दूसरी ओर सिंचाई व्यवस्था की हालत भी चिंताजनक है, बांध और नहरें रखरखाव के अभाव में दम तोड़ रही हैं,किसान पूछ रहे हैं कि यदि पानी ही नहीं मिलेगा तो खेती कैसे होगी? लेकिन इन सवालों का जवाब किसी मंच से सुनाई नहीं देता।

सेमरिया की पुलियाः प्रशासन हादसे का इंतजार कर रहा है?

सेमरिया की टूटी पुलिया पिछले एक साल से ग्रामीणों के लिए खतरा बनी हुई है, हर दिन स्कूली बच्चे, बुजुर्ग और आम नागरिक जान जोखिम में डालकर यहां से गुजरते हैं, लेकिन मरम्मत की दिशा में कोई ठोस पहल नहीं दिखाई देती,ऐसा लगता है मानो जिम्मेदार विभाग किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहा हो ताकि उसके बाद संवेदनाओं की प्रेस विज्ञप्ति जारी की जा सके।

सुशासन या सिर्फ आयोजन?

कोरिया जन सहयोग समिति के कार्यकारी अध्यक्ष अधिवक्ता जयचंद सोनपाकर का सवाल पूरे क्षेत्र की भावना को व्यक्त करता है, यदि समाधान शिविरों के बाद भी समस्याएं जस की तस हैं...यदि मुख्यालय अंधेरे में है...यदि नेटवर्क गायब है...यदि आदिवासी प्रमाण पत्र के लिए भटक रहे हैं...यदि गांव बिजली से वंचित हैं...यदि पुलिया टूटी है...तो फिर सुशासन आखिर कहां है? क्या वह केवल मंच पर था? क्या वह केवल भाषणों में था? या फिर वह फाइलों के किसी ऐसे पन्ने में बंद है जिसे जनता कभी देख ही नहीं सकती? सोनहत की जनता अब आश्वासनों से आगे बढ़कर परिणाम चाहती है,क्योंकि सुशासन का अर्थ तालियों की गूंज नहीं, बल्कि समस्याओं का समाधान होता है, और जब समस्याएं वर्षों तक जस की तस खड़ी रहें,तब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर यह सुशासन है या केवल उसका उत्सव? सोनहत आज भी जवाब का इंतजार कर रहा है।

दो सुशासन तिहार बीते,तीन साल गुजर गए...बिजली आज भी रास्ते में है!

नेटवर्क गायब,बिजली अधूरी,स्ट्रीट लाइट बंद, पुलिया टूटी और आदिवासी प्रमाण-पत्र के लिए भटकते रहे–फिर भी सफल रहा सुशासन तिहार!

सुशासन तिहार का शोर,समस्याओं का सन्नाटा,सोनहत आज भी अंधेरे, प्यास और इंतजार में...

मंच पर सुशासन,जमीन पर बदहाली सोनहत की जनता पूछ रही–समाधान कहां है?

डिजिटल इंडिया के पोस्टर में सोनहत, हकीकत में नेटवर्क खोजता रामगढ़

आवेदन लिए गए, आश्वासन दिए गए... लेकिन सोनहत को मिला क्या?

सुशासन तिहार का जश्न खत्म, अब जनता पूछ रही है–बिजली, पानी, सड़क और नेटवर्क कब मिलेगा?

भाषणों में विकास, हकीकत में अंधकार, सोनहत में सुशासन के दावों की खुली पोल

ब्लॉक मुख्यालय में ही अंधेरा,फिर गांवों का क्या होगा?-

सबसे बड़ा व्यंग्य यह है कि जिस ब्लॉक मुख्यालय से पूरे क्षेत्र के विकास की दिशा तय होती है, वहीं शाम होते ही अंधेरा राज करने लगता है, सोनहत की स्ट्रीट लाइटें वर्षों से बंद पड़ी हैं, कई खंभे ऐसे खड़े हैं जैसे विकास की समाधि पर पहरा दे रहे हों, दिन में वे सरकारी योजनाओं की सफलता के प्रतीक लगते हैं और रात में प्रशासनिक लापरवाही की गवाही देते हैं, सुशासन तिहार में करोड़ों की योजनाओं के दावे सुनने को मिले,लेकिन मुख्यालय की सड़कें रोशन करने के लिए कोई घोषणा नहीं हुई,लगता है अंधेरे को भी अब सरकारी संरक्षण प्राप्त हो चुका है, स्थानीय लोग तंज कसते हैं कि शायद स्ट्रीट लाइटें भी किसी अगले सुशासन तिहार का इंतजार कर रही हैं।

डिजिटल इंडिया के पोस्टर में रामगढ़,लेकिन नेटवर्क में गायब

देश चांद पर पहुंच चुका है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की चर्चा हो रही है,डिजिटल इंडिया के विज्ञापन हर तरफ दिखाई देते हैं, लेकिन सोनहत के रामगढ़ क्षेत्र में मोबाइल नेटवर्क आज भी लुकाछिपी का खेल खेल रहा है,टावर खड़े हैं, लेकिन सिग्नल नहीं,खंभे दिखाई देते हैं, लेकिन बातचीत नहीं, नेटवर्क चालू बताया जाता है,लेकिन जनता कहती है कि यह चालू होकर भी बंद के बराबर है,स्थिति ऐसी है कि कई गांवों में लोगों को फोन करने के लिए पहाड़ी पर चढ़ना पड़ता है,इंटरनेट चलाने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता है, ऑनलाइन पढ़ाई,डिजिटल भुगतान और ई-गवर्नेंस जैसी बातें यहां मजाक जैसी लगती हैं,डिजिटल इंडिया का सपना यहां नेटवर्क खोजते-खोजते दम तोड़ता नजर आता है।

राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र,लेकिन प्रमाण-पत्र के लिए बेबस

पंडो जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा प्राप्त है,सरकारी दस्तावेजों और भाषणों में इनके उत्थान की बातें खूब होती हैं,लेकिन सोनहत की हकीकत कुछ और कहानी कहती है,जाति और निवास प्रमाण पत्र के लिए पंडो परिवार वर्षों से भटक रहे हैं,नई पीढ़ी उच्च शिक्षा से वंचित हो रही है, कई युवाओं को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा, सरकारी योजनाएं कागजों में हैं, लेकिन लाभार्थी सूची तक पहुंचने से पहले ही लोग दफ्तरों के चक्कर लगाते-लगाते थक जाते हैं,विडंबना देखिए,जिन्हें शासन दत्तक पुत्र बताता है,वे आज भी अपनी पहचान साबित करने के लिए सरकारी दफ्तरों के सामने खड़े हैं।

तीन साल,दो सुशासन तिहार और बिजली अब भी रास्ते में

चंदहा, बंशीपुर और कचोहर गांवों का विद्युतीकरण अब विकास से ज्यादा धैर्य परीक्षा का विषय बन चुका है,तीन साल गुजर गए, दो सुशासन तिहार निकल गए, कई शिविर लगे,अनगिनत आवेदन दिए गए, लेकिन बिजली अब भी फाइलों के जंगल में रास्ता तलाश रही है, ग्रामीण बताते हैं कि हर बार आश्वासन मिलता है,हर बार सर्वे होता है, हर बार अधिकारी आते हैं,तस्वीरें खिंचती हैं और फिर सब कुछ अगले वर्ष तक स्थगित हो जाता है,यदि आश्वासन से बल्ब जलते तो शायद इन गांवों में आज चौबीसों घंटे रोशनी होती।

पटना तहसील में कथित रिश्वतखोरी का आरोप, कलेक्टर से शिकायत कर जांच की मांग

भूमि प्रकरण में तहसीलदार और कोटवार पर पैसे लेने का आरोप,आवेदक ने एफआईआर दर्ज करने की मांग उठाई...

-संवाददाता-

बैकुंठपुर,12 जून 2026 (घटती-घटना)।

जिला कलेक्टर को सौंपे गए एक शिकायत पत्र में पटना तहसील के तहसीलदार एवं एक कोटवार पर कथित रूप से रिश्वत लेने तथा भूमि संबंधी प्रकरण में अनियमितता करने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं, शिकायतकर्ता ने मामले की निष्पक्ष जांच कराने,संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने तथा कथित रूप से लिए गए पैसों की वापसी सुनिश्चित करने की मांग की है।शिकायतकर्ता रामचंद्र (शोभई) राम, निवासी ग्राम तेजपुर,तहसील रामानुजनगर,जिला सूरजपुर ने कलेक्टर को दिए आवेदन में आरोप लगाया है कि उनकी भूमि से जुड़े एक प्रकरण में सुनवाई के दौरान पटना क्षेत्र के एक कोटवार ने उन्हें मामले में पक्ष में निर्णय दिलाने का भरोसा देते हुए पैसे की मांग की,

शिकायतकर्ता का आरोप है कि उन्होंने कथित रूप से तहसीलदार को 10 हजार रुपये तथा कोटवार को भी 10 हजार रुपये दिए, आवेदन में यह भी आरोप लगाया गया है कि बाद में उन्हें जानकारी मिली कि भूमि प्रकरण में नाम जोड़ने के लिए कथित रूप से एक लाख रुपये तक की राशि ली गई, शिकायतकर्ता ने अपने आवेदन में यह भी दावा किया है कि तहसील कार्यालय में बिचौलियों की सक्रियता है और न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित हो रही है, शिकायतकर्ता ने कलेक्टर से मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने, संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने तथा कथित रूप से दिए गए 20 हजार रुपये वापस दिलाने की मांग की है, मामला सामने आने के बाद क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है, हालांकि समाचार लिखे जाने तक शिकायत में लगाए गए आरोपों पर संबंधित तहसीलदार अथवा अन्य पक्षों का आधिकारिक पक्ष प्राप्त नहीं हो सका था,यदि शिकायत में लगाए गए आरोप सही पाए जाते हैं तो यह मामला राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली और पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर सकता है, वहीं दूसरी ओर, जांच पूरी होने तक आरोपों की सत्यता की पुष्टि होना बाकी है।

सरपदह नाला निर्माण का भुगतान अटका,पूर्व उपसरपंच ने कलेक्टर से लगाई न्याय की गुहार

छिंदिया पंचायत में वर्ष 2018-19 के निर्माण कार्य की 5.81 लाख रुपये से अधिक की बकाया राशि भुगतान की मांग...

-संवाददाता-

बैकुंठपुर, 12 जून 2026 (घटती-घटना)।

ग्राम पंचायत छिंदिया में वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्वीकृत सरपदह नाला निर्माण कार्य का भुगतान वर्षों बाद भी लंबित होने का मामला सामने आया है,पंचायत के पूर्व उपसरपंच चन्द्र प्रकाश यादव ने कलेक्टर को आवेदन सौंपकर निर्माण कार्य में उपयोग की गई सामग्री की बकाया राशि का भुगतान कराने की मांग की है,शिकायत सामने आने के बाद पंचायत स्तर पर कराए गए निर्माण कार्यों के भुगतान और वित्तीय प्रबंधन को लेकर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं।

कलेक्टर को सौंपे गए आवेदन में पूर्व उपसरपंच चन्द्र प्रकाश यादव ने बताया है कि वह वर्ष 2020 से 2025 तक ग्राम पंचायत छिंदिया में उपसरपंच के पद पर कार्यरत रहे, उनके अनुसार तत्कालीन सरपंच द्वारा पंचायत लेटरपैड के माध्यम से उन्हें निर्माण कार्यों की निगरानी और सामग्री व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, उन्होंने निर्माण कार्य के लिए आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई तथा कार्यों का पर्यवेक्षण भी किया,आवेदन के अनुसार सरपदह नाला निर्माण कार्य में प्रयुक्त सामग्री के एवज में पंचायत द्वारा कुछ राशि का भुगतान किया गया,लेकिन पूरी राशि का भुगतान आज तक नहीं किया गया है, शिकायतकर्ता का कहना है कि भुगतान लंबित रहने के कारण सामग्री आपूर्तिकर्ताओं और व्यापारियों का दबाव लगातार उन पर बढ़ता जा रहा है तथा उन्हें आर्थिक और सामाजिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, आवेदन में भुगतान का पूरा विवरण भी प्रस्तुत किया गया है,शिकायत के अनुसार विभिन्न तिथियों में कुल 7 लाख 39 हजार 624 रुपये का भुगतान किया गया है। इसके बावजूद 5 लाख 81 हजार 953 रुपये 36 पैसे की राशि अब भी बकाया है, जिसका भुगतान नहीं किया गया है, शिकायतकर्ता ने दावा किया है कि कई बार पंचायत और संबंधित अधिकारियों के समक्ष भुगतान की मांग रखी गई,लेकिन आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, पूर्व उपसरपंच ने कलेक्टर से मांग की है कि मामले की जांच कर बकाया भुगतान की व्यवस्था कराई जाए,उनका कहना है कि निर्माण कार्य वर्षों पहले पूरा हो चुका है, लेकिन भुगतान लंबित रहने से उन्हें लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है,यह मामला ऐसे समय सामने आया है जब पंचायत स्तर पर विकास कार्यों के भुगतान, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और वित्तीय पारदर्शिता को लेकर समय-समय पर सवाल उठते रहे हैं,यदि शिकायत में किए गए दावे सही पाए जाते हैं तो यह पंचायतों में निर्माण कार्यों के भुगतान तंत्र और जवाबदेही पर गंभीर प्रश्न खड़े कर सकता है, स्थानीय लोगों का भी कहना है कि विकास कार्यों के लिए सामग्री उपलब्ध कराने वाले लोगों का भुगतान वर्षों तक लंबित रहना उचित नहीं है,यदि किसी व्यक्ति ने पंचायत के निर्देश पर कार्य कराया है तो उसका भुगतान समय पर होना चाहिए, वहीं दूसरी ओर, प्रशासनिक स्तर पर यह भी आवश्यक है कि भुगतान से जुड़े सभी दस्तावेजों और दावों की निष्पक्ष जांच की जाए ताकि वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सके, फिलहाल मामला कलेक्टर कार्यालय पहुंच चुका है और अब शिकायतकर्ता सहित स्थानीय लोगों की निगाहें जिला प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी हुई हैं, देखना होगा कि वर्षों पुराने इस भुगतान विवाद का समाधान कब तक हो पाता है और शिकायतकर्ता को राहत मिलती है या नहीं।

C M Y K

मेडिकल कॉलेज पर सियासत गरम

क्या सचमुच अटक गया मनेंद्रगढ़ का सपना,या एनएमसी की सामान्य प्रक्रिया को बनाया जा रहा है राजनीतिक हथियार?

मेडिकल कॉलेज पर सियासत तेज, एनएमसी की आपत्तियों के बीच उम्मीदें बरकरार,आरोप-प्रत्यारोप जारी

मनेंद्रगढ़ मेडिकल कॉलेज पर घमासान,विपक्ष ने बताया विफलता, सरकार बोली...यह सामान्य प्रक्रिया

क्या अटक गया मेडिकल कॉलेज का सपना? एनएमसी की आपत्तियों पर आमने-सामने सत्ता और विपक्ष?

220 बिस्तरों का अस्पताल तैयार, निर्माण जारी फिर क्यों उठ रहे मेडिकल कॉलेज पर सवाल?

एनएमसी की कमियों पर सियासत गर्म,मेडिकल कॉलेज बंद नहीं,प्रक्रिया में है मंजूरी

ऐसा बनेगा मनेंद्रगढ़ का मेडिकल कालेज की

निर्माणाधीन मनेंद्रगढ़ मेडिकल कालेज

-रवि सिंह-

एमसीबी, 12 जून 2026 (घटती-घटना)।

मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले में मेडिकल कॉलेज को लेकर एक बार फिर राजनीतिक तापमान बढ़ गया है,एक अखबार में प्रकाशित खबर में दावा किया गया कि छत्तीसगढ़ के पांच प्रस्तावित मेडिकल कॉलेजों को नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) से मंजूरी नहीं मिल सकी है,खबर सामने आते ही विपक्ष ने इसे सरकार की विफलता करार दिया,जबकि सत्ता पक्ष ने इसे सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया बताते हुए कहा कि मेडिकल कॉलेज की मान्यता पर किसी प्रकार की अंतिम रोक नहीं लगी है, इस पूरे विवाद के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर मनेंद्रगढ़ मेडिकल कॉलेज की वास्तविक स्थिति क्या है? क्या मेडिकल कॉलेज का सपना टूट गया है या फिर यह केवल मान्यता की प्रक्रिया में आने वाली तकनीकी बाधा है, जिसे समय के साथ दूर कर लिया जाएगा?

फिर विवाद क्यों खड़ा हुआ? : पूर्व विधायक गुलाब कमरो

विवाद की शुरुआत उस समय हुई जब खबर सामने आई कि एनएमसी ने प्रस्तावित मेडिकल कॉलेजों में कुछ कमियां पाई हैं, खबर में अस्पताल और भवन संबंधी कमियों का उल्लेख किया गया,जिसके बाद विपक्ष को सरकार पर हमला बोलने का मौका मिल गया, पूर्व विधायक गुलाब कमरो ने इसे डबल इंजन सरकार की बड़ी विफलता बताते हुए कहा कि मेडिकल कॉलेज के नाम पर जनता को भ्रमित किया गया,उन्होंने आरोप लगाया कि यदि तैयारियां पूरी थीं तो एनएमसी ने आपत्तियां क्यों लगाईं,कमरो ने कहा कि मेडिकल कॉलेज से क्षेत्र के युवाओं और मरीजों को बड़ी उम्मीदें थीं,लेकिन सरकार उन उम्मीदों पर खरी उतरती दिखाई नहीं दे रही है।

यह कोई असामान्य घटना नहीं : प्रवक्ता डॉ. विजय शंकर मिश्रा

भाजपा और सरकार का पक्ष इससे बिल्कुल अलग है, भाजपा प्रदेश प्रवक्ता डॉ. विजय शंकर मिश्रा ने स्पष्ट कहा है कि एनएमसी द्वारा बताई गई कमियां किसी भी नए मेडिकल कॉलेज की मान्यता प्रक्रिया का सामान्य हिस्सा होती हैं, निरीक्षण के दौरान भवन, उपकरण, फैकल्टी, प्रयोगशालाओं और अन्य सुविधाओं की जांच होती है। यदि कहीं कमी मिलती है तो उसे दूर करने का अवसर दिया जाता है,सरकार का दावा है कि जो कमियां बताई गई हैं,उन्हें दूर करने की प्रक्रिया पहले से जारी है और अंतिम मान्यता प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है।

राजनीतिक बयान और जमीनी सच्चाई...

राजनीति में अक्सर उपलब्धियों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जाता है और कमियों को बड़ा मुद्दा बना दिया जाता है,मेडिकल कॉलेज के मामले में भी कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है,विपक्ष इस मुद्दे को सरकार की नाकामी के रूप में प्रस्तुत कर रहा है,जबकि सरकार इसे प्रक्रिया का हिस्सा बता रही है,लेकिन जमीनी सच्चाई यह है कि मेडिकल कॉलेज के लिए निर्माण कार्य हुआ है,अस्पताल तैयार है और परियोजना अस्तित्व में है,दूसरी सच्चाई यह भी है कि एनएमसी ने कुछ कमियां बताई हैं,जिन्हें पूरा किए बिना अंतिम मंजूरी मिलना संभव नहीं होगा, यानी मामला न तो पूरी तरह विफलता का है और न ही पूर्ण सफलता का।

अब आगे क्या होगा?

आने वाले महीनों में यह स्पष्ट हो जाएगा कि सरकार एनएमसी द्वारा बताई गई कमियों को कितनी तेजी से दूर कर पाती है,यदि आवश्यक सुधार समय पर पूरे हो जाते हैं तो मेडिकल कॉलेज को मान्यता मिलने का रास्ता साफ हो सकता है,लेकिन यदि प्रक्रिया लंबी खिंचती है तो राजनीतिक विवाद और तीखा होगा।

परियोजना अभी समाप्त नहीं,मान्यता प्रक्रिया जारी है...

मनेंद्रगढ़ मेडिकल कॉलेज को लेकर फैली निराशा और राजनीतिक बयानबाजी के बीच एक तथ्य सबसे महत्वपूर्ण है,यह परियोजना अभी समाप्त नहीं हुई है,मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य चल चुका है,220 बिस्तरों वाला अस्पताल तैयार है और मान्यता प्रक्रिया जारी है,एनएमसी द्वारा बताई गई कमियां निश्चित रूप से गंभीर हैं,क्योंकि बिना उन्हें पूरा किए मेडिकल कॉलेज शुरू नहीं हो सकता,लेकिन यह भी उतना ही सच है कि देश और प्रदेश के अनेक मेडिकल कॉलेज इसी प्रकार की आपत्तियों और सुधार प्रक्रियाओं से गुजरकर ही अस्तित्व में आए हैं,इसलिए फिलहाल यह कहना कि मेडिकल कॉलेज नहीं खुलेगा,जल्दबाजी होगी,वहीं यह कहना भी उचित नहीं होगा कि सब कुछ पूरी तरह तैयार है और कोई समस्या नहीं है, अब जिले की जनता को राजनीतिक बयान नहीं,बल्कि एक ही जवाब चाहिए मनेंद्रगढ़ मेडिकल कॉलेज कब शुरू होगा? यही सवाल आने वाले समय में सरकार,स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन के सामने सबसे बड़ी परीक्षा बनकर खड़ा रहेगा।

जिस मेडिकल कॉलेज को लेकर वर्षों से इंतजार था...

एमसीबी जिला बनने के बाद से ही क्षेत्रवासियों की सबसे बड़ी मांगों में मेडिकल कॉलेज शामिल रहा है,जिले के लोगों को उम्मीद थी कि मेडिकल कॉलेज बनने से न केवल स्थानीय युवाओं को चिकित्सा शिक्षा मिलेगी बल्कि स्वास्थ्य सुविधाओं का भी विस्तार होगा,सरकार द्वारा मेडिकल कॉलेज की घोषणा के बाद निर्माण कार्य शुरू हुआ,मेडिकल कॉलेज से संबद्ध लगभग 220 बिस्तरों वाला सिविल अस्पताल भी तैयार किया गया,अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं संचालित हो रही हैं और मेडिकल कॉलेज परिसर के निर्माण का कार्य भी आगे बढ़ा है,यानी स्थिति यह नहीं है कि केवल कागजों में मेडिकल कॉलेज की घोषणा हुई हो,जमीनी स्तर पर अधोसंरचना निर्माण और अस्पताल संचालन का काम पहले से चल रहा है।

एनएमसी आखिर देखता क्या है?

कई लोगों को यह भ्रम है कि भवन बन गया तो मेडिकल कॉलेज शुरू हो जाएगा, वास्तविकता इससे कहीं अधिक जटिल है,एनएमसी किसी भी मेडिकल कॉलेज को मान्यता देने से पहले दर्जनों बिंदुओं की जांच करता है,इसमें अस्पताल में मरीजों की संख्या,विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता, शिक्षकों की नियुक्ति,प्रयोगशालाएं,उपकरण,पुस्तकालय,छात्रावास, व्याख्यान कक्ष और अन्य सुविधाएं शामिल होती हैं,कई बार भवन पूरी तरह तैयार होने के बाद भी फैकल्टी या उपकरण संबंधी कमियां रह जाती हैं, ऐसे मामलों में एनएमसी आपत्तियां दर्ज करता है और सुधार का समय देता है,इसलिए निरीक्षण में कमियां मिलना सीधे तौर पर मेडिकल कॉलेज रद्द होने का संकेत नहीं माना जाता।

अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज भी इसी प्रक्रिया से गुजरा था...

राजनीतिक बयानबाजी के बीच एक तथ्य यह भी है कि छत्तीसगढ़ में पहले भी मेडिकल कॉलेज इसी प्रकार की प्रक्रिया से गुजर चुके हैं,अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज के शुरुआती दौर में भी निरीक्षण के दौरान विभिन्न आपत्तियां सामने आई थीं,कई तकनीकी और अधोसंरचनात्मक बिंदुओं पर सुधार के निर्देश दिए गए थे,बाद में कमियां दूर की गईं और कॉलेज को मान्यता प्राप्त हुई,स्वास्थ्य क्षेत्र के जानकारों का कहना है कि देश के अधिकांश नए मेडिकल कॉलेज प्रारंभिक निरीक्षण में आपत्तियों का सामना करते हैं, इसलिए केवल आपत्तियों के आधार पर किसी परियोजना को विफल घोषित करना उचित नहीं होगा।

जनता का सवाल फिर भी जायज है...

हालांकि सरकार का पक्ष अपनी जगह है,लेकिन जनता के कुछ सवाल भी पूरी तरह उचित हैं,यदि मेडिकल कॉलेज की मान्यता प्रक्रिया जारी थी तो यह स्पष्ट जानकारी पहले क्यों नहीं दी गई? यदि कुछ कमियां शेष थीं तो कॉलेज जल्द शुरू होने के दावे क्यों किए गए? जनता जानना चाहती है कि एनएमसी ने वास्तव में कौन-कौन सी कमियां बताई हैं और उन्हें दूर करने में कितना समय लगेगा, यह पारदर्शिता सरकार और स्वास्थ्य विभाग दोनों के लिए आवश्यक है।

सियासत के केंद्र में स्वास्थ्य का मुद्दा...

मेडिकल कॉलेज का विषय केवल राजनीतिक मुद्दा नहीं है। यह सीधे तौर पर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ा हुआ मामला है,मनेंद्रगढ़,चिरमिरी,भरतपुर और आसपास के क्षेत्रों के हजारों छात्र मेडिकल शिक्षा के लिए बड़े शहरों का रुख करने को मजबूर होते हैं, मेडिकल कॉलेज शुरू होने से स्थानीय छात्रों को बड़ा लाभ मिलेगा,इसके अलावा गंभीर मरीजों को अंबिकापुर, बिलासपुर, रायपुर और अन्य शहरों तक रेफर करने की मजबूरी भी कम हो सकती है, यही कारण है कि जनता इस परियोजना को केवल चुनावी घोषणा नहीं बल्कि भविष्य की आवश्यकता के रूप में देख रही है।

किसानों के समर्थन में सड़क पर उतरी कांग्रेस,सरकार पर लगाए किसान विरोधी नीतियों के आरोप

खाद,बीज और डीजल की मांग को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन,आंदोलन तेज करने की चेतावनी,खड़गवां में कांग्रेस का चक्काजाम,किसानों की समस्याओं को लेकर सरकार को घेरा

-संवाददाता-

एमसीबी/खड़गवां, 12 जून 2026 (घटती-घटना)।

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार जिला कांग्रेस कमेटी एमसीबी के नेतृत्व में खड़गवां में किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर चक्काजाम एवं किसान आंदोलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व पूर्व विधायक गुलाब कमरो एवं जिला कांग्रेस कमेटी एमसीबी के अध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव ने किया।

आंदोलन में जिला कांग्रेस, ब्लॉक कांग्रेस, महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस, एनएसयूआई, आदिवासी कांग्रेस, ओबीसी कांग्रेस तथा किसान कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किसानों की समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया, चक्काजाम किया तथा राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए किसानों के हित में ठोस कदम उठाने की मांग की।

किसानों को खाद-बीज के लिए भटकना पड़ रहा : अशोक श्रीवास्तव

सभा को संबोधित करते हुए जिला कांग्रेस कमेटी एमसीबी के अध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव ने कहा कि प्रदेश के किसान वर्तमान समय में खाद, बीज और डीजल जैसी बुनियादी आवश्यकताओं के लिए परेशान हैं, समय पर कृषि सामग्री उपलब्ध नहीं होने के कारण खेती-किसानी प्रभावित हो रही है और किसानों की आर्थिक स्थिति लगातार कमजोर होती जा रही है, उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार की किसान विरोधी नीतियों के कारण किसानों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, कांग्रेस पार्टी किसानों की आवाज बनकर उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ती रहेगी और जरूरत पड़ने पर आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

किसानों के अधिकारों की लड़ाई जारी रहेगी : गुलाब कमरो

पूर्व विधायक गुलाब कमरो ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों के हितों की रक्षा के लिए संघर्ष करती रही है,उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसान आज खाद,बीज और डीजल जैसी आवश्यक सुविधाओं के लिए भटकने को मजबूर हैं,जबकि सरकार उनकी समस्याओं के समाधान के प्रति गंभीर नजर नहीं आ रही है, उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि किसानों की समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं किया गया तो कांग्रेस पार्टी आंदोलन को और व्यापक रूप देगी तथा किसानों के अधिकारों की रक्षा के लिए सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेगी।

तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन

कार्यक्रम के समापन पर कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने खड़गवां तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा,ज्ञापन में किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद एवं बीज उपलब्ध कराने,डीजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा कृषि संकट के निराकरण के लिए तत्काल प्रभावी कदम उठाने की मांग की गई।

किसानों के हित में संघर्ष जारी रखने का संकल्प

आंदोलन में उपस्थित नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने किसानों के हितों की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया,कांग्रेस नेताओं ने सरकार से मांग की कि किसानों की समस्याओं का तत्काल समाधान किया जाए ताकि कृषि कार्य प्रभावित न हो और किसानों को राहत मिल सके,कार्यक्रम में जिले भर से कांग्रेस संगठन के विभिन्न प्रकोष्ठों के पदाधिकारी,जनप्रतिनिधि एवं कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

इस सुपरहिट फिल्म के सेट पर कटरीना कैफ और रणबीर कपूर के बीच शुरू हुई थी प्रेम की कहानी?

कटरीना कैफ और रणबीर कपूर के बीच डेटिंग की खबरों ने खूब ध्यान खींचा था। अब को-स्टार ने खुलासा किया है कि 17 साल पुरानी फिल्म से उनकी प्रेम कहानी शुरू हुई थी भी या नहीं। बॉलीवुड अभिनेता रणबीर कपूर और अभिनेत्री कटरीना कैफ ने एक साथ अजब प्रेम की गजब कहानी,जग्गा जासूस और राजनीति में काम किया था। जितनी उनकी ऑन-स्क्रीन जोड़ी चर्चा में रही, उतना ऑफ-स्क्रीन रोमांस ने भी सुर्खियां बटोरी थीं।

कहा जाता है कि रणबीर कपूर और कटरीना कैफ ने सालों तक एक-दूसरे को डेट किया था और उनके प्यार की दास्तां 17 साल पुरानी फिल्म से शुरू हुई थी। हालांकि, अब दोनों के को-स्टार ने इन अफवाहों पर फुल स्टॉप लगाया है।

कटरीना-रणबीर की पहली फिल्म

रणबीर और कटरीना ने पहली फिल्म 2009 में रोम-कॉम ड्रामा अजब प्रेम की गजब कहानी की थी। ऐसी खबरें थीं कि इसी फिल्म के सेट पर दोनों के बीच इश्क की शुरुआत

हुई थी। अब एक्टर विश्वनाथ ने बताया है कि क्या वाकई सेट पर रियल लाइफ में दोनों के बीच रोमांस चलता था या नहीं।

क्या सेट पर था कटरीना-रणबीर का रोमांस?

विश्वनाथ ने सिद्धार्थ कन्नन के साथ बातचीत में इन अफवाहों को खारिज कर दिया। जब उनसे पूछा गया कि अजब प्रेम की कहानी, जो रणबीर कपूर और कटरीना कैफ की मोहब्बत थी, उसी सेट से शुरू हुआ था। क्या देखा था आप ने सेट पर? इस पर एक्टर ने कहा-सेट पर कुछ नहीं हो रहा था। सर,राजकुमार संतोषी जी बैठे हैं वहां,उनके सामने कुछ हो सकता है? सारेलोग वहां पर बहुत आज्ञाकारी बच्चे थे। राजकुमार संतोषी सर किंग हैं,शेर हैं वो। वो इतना अपनी कहानी और कैरेक्टर में लोगों को घुसाकर रखते थे और लोगों को बहुत पैंपर करते थे। ऐसा हमने कुछ नहीं देखा।

कटरीना की फिटनेस से हैरान थे रणबीर

कटरीना कैफ की फिटनेस की तारीफ करते हुए एक्टर ने कहा, हम लोग ना, सब दोस्त और रणबीर खुद,कटरीना की डेडीकेशन और फिजिकल फिटनेस देखकर हैरान थे। एक सीन था जिसमें उन्हें एक बोट से सीढ़ी चढ़नी थी और ब्रिज पर पहुंचना था। कटरीना जी एकदम जल्दी चढ़ गईं। उन्होंने अपनी स्पीच पर भी बहुत मेहनत की। डेडीकेशन के मामले में कटरीना जी टॉप नंबर पर थे पूरी टीम में। हम लोगों ने बहुत मस्ती की।

उर्वशी रौतेला को चाहिए संस्कारी लड़का

एक्ट्रेस ने बताया लाइफ पार्टनर में होनी चाहिए ये खूबियां

उर्वशी रौतेला ने अपने आदर्श जीवनसाथी के बारे में बात की है,जिसमें उन्होंने बताया कि उन्हें बाहरी आकर्षण से ज्यादा पारिवारिक मूल्य और अच्छे संस्कार वाला पार्टनर चाहिए।

उर्वशी रौतेला हाल ही में ओटीटी सीरीज इंस्पेक्टर अविनाश पार्ट 2 में नजर आई थीं। उर्वशी ने इसमें पूनम मिश्रा की भूमिका निभाई थी। हाल ही में एक्ट्रेस ने अपने लाइफ पार्टनर और जिंदगी में किस एक्टर को वो अपना हमसफर बनाना चाहेंगी इस पर बात की।

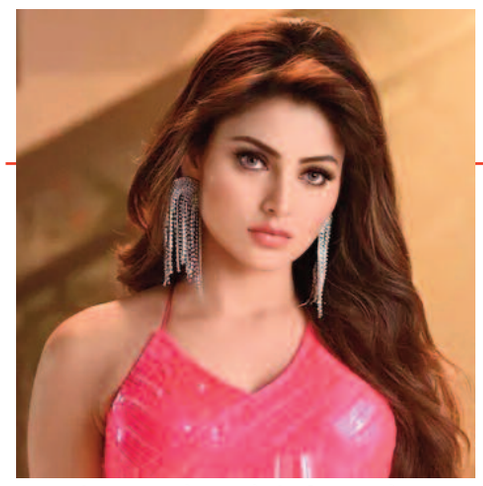

क्या इंडस्ट्री से अपना हमसफर चुनेंगी उर्वशी

किसी भी रिश्ते में बाहरी आकर्षण से ज्यादा अभिनेत्री उर्वशी रौतेला के लिए पारिवारिक मूल्य मायने रखते हैं। उर्वशी मानती हैं कि उन्हें पसंद करने वालों की कमी नहीं है, लेकिन जीवनसाथी के रूप में वह ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहेंगी जो अच्छे संस्कारों वाला हो। यही वजह है कि वह फिल्म इंडस्ट्री के बजाय अभिनय जगत से बाहर के किसी शख्स को अपना हमसफर बनाने के पक्ष में हैं।

कौन है उर्वशी की पसंद?

उर्वशी कहती हैं कि जो इंसान मुझे नजदीकी से जानेगा,उसे मुझसे मोहब्बत हो जाएगी। कई लड़के हैं, जो मुझे पसंद करते हैं, लेकिन मेरे लिए यह मायने नहीं रखता है कि लड़का कैसा दिखता है। मेरे लिए पारिवारिक मूल्य मायने रखते हैं। वह कितना जिम्मेदार है, अपनी कही बातों पर कितना खरा उतरता है, यह देखना भी जरूरी है। कई लड़के होते हैं, जो किसी भी तरह का कमिटमेंट यानी वादा करने से डरते हैं, लेकिन जिन्हें अच्छे पारिवारिक संस्कार मिले होंगे, वे इन चीजों से नहीं डरेंगे।

क्या उर्वशी फिल्म इंडस्ट्री से ही अपने लिए हमसफर चुनेंगी या इंडस्ट्री के बाहर से?

इस पर वह कहती हैं कि मुझे लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री से अगर कोई होगा तो मेरे परिवार वाले ही उसे नहीं अपनाएंगे। वे चाहते हैं कि अभिनय के पेशे के बाहर से कोई हो। मैं भी यही चाहती हूं,क्योंकि इसे पेशे से बाहर का अगर कोई होगा तो उसके साथ घर जाने पर बातें करने के लिए कई और चीजें होंगी।

500 रुपए लेकर मुंबई आई थीं दिशा पाटनी, संघर्ष से लिखी सफलता की कहानी...

बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी की गिनती उन अभिनेत्रियों में होती है,जिन्होंने कम समय में अपनी अलग पहचान बनाई है। हालांकि,उनकी सफलता की कहानी उतनी आसान नहीं रही,जितनी बाहर से लोगों को दिखाई देती है। बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए काफी संघर्ष किया है। एक समय ऐसा भी था जब वह बेहद कम पैसों के साथ मुंबई आई थीं और मेहनत के दम पर ये मुकाम हासिल किया। दिशा पाटनी का जन्म 13 जून 1992 को उत्तर प्रदेश के बरेली में हुआ था। उनका परिवार मूल रूप से उत्तराखंड के टनकपुर से जुड़ा हुआ है। उनके पिता जगदीश सिंह पाटनी पुलिस विभाग में अधिकारी रहे,जबकि उनकी मां स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत थीं। बचपन से ही दिशा पढ़ाई में अच्छी थीं। उन्होंने कभी अभिनेत्री बनने का सपना नहीं देखा था। वह एयरफोर्स पायलट या साइंसटिस्ट बनना चाहती थीं। उन्होंने इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई की। कॉलेज के दिनों में उनकी जिंदगी ने नया मोड़ लिया। एक दोस्त ने उन्हें मॉडलिंग कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने की सलाह दी, जिसमें उन्होंने जीत हासिल की। इसके बाद उन्हें मॉडलिंग के कई मौके मिलने लगे। धीरे-धीरे विज्ञापन जगत में भी उनकी पहचान बनने लगी। उन्होंने कई विज्ञापनों में काम किया। कैमरे के सामने एक्टिंग करने के इस अनुभव ने उन्हें फिल्मों में लाकर खड़ा कर दिया। दिशा ने अपने संघर्ष के दिनों को याद करते हुए एक इंटरव्यू में बताया था कि वह केवल 500 रुपए लेकर मुंबई पहुंची थीं। उस समय उनके पास कोई बड़ा सहारा नहीं था। उन्होंने परिवार से आर्थिक मदद लेने के बजाय खुद मेहनत करके आगे बढ़ने का फैसला किया। मुंबई जैसे बड़े शहर में रहना आसान नहीं था,लेकिन दिशा ने हार नहीं मानी। उन्होंने लगातार ऑडिशन दिए, मॉडलिंग की और अपने सपनों को सच करने के लिए दिन-रात मेहनत की। यही संघर्ष बाद में उनकी सफलता की सबसे बड़ी ताकत बना। साल 2015 में दिशा को पहली बड़ी सफलता तेलुगु फिल्म लोफर से मिली। इस फिल्म में उनके काम को सराहा गया। इसके बाद साल 2016 में उन्हें हिंदी फिल्म एमएस धोनी- द अनटोल्ड स्टोरी में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म में उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी की पहली प्रेमिका प्रियंका झा का किरदार निभाया था। भले ही उनका रोल लंबा नहीं था,लेकिन उनके अभिनय ने दर्शकों का दिल जीत लिया। इसके बाद दिशा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने कुंग फू योगा,बागी 2,भारत,मलंग,राधे,एक विलेन रिटर्न्स, योद्धा और कल्कि 2898 एडी जैसी फिल्मों में काम किया। एक्शन, रोमांस और ग्लैमर से भरपूर किरदारों के जरिए उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। वह अपनी फिटनेस को लेकर भी हमेशा चर्चा में बनी रहती हैं।

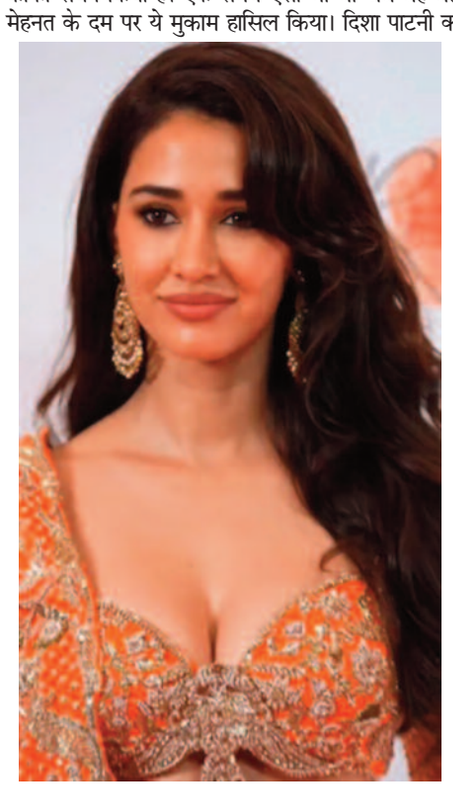

2 साल तक बॉलीवुड में रहा बेरोजगार,बाद में बांग्लादेश का अमिताभ बच्चन बना ये सुपरस्टार

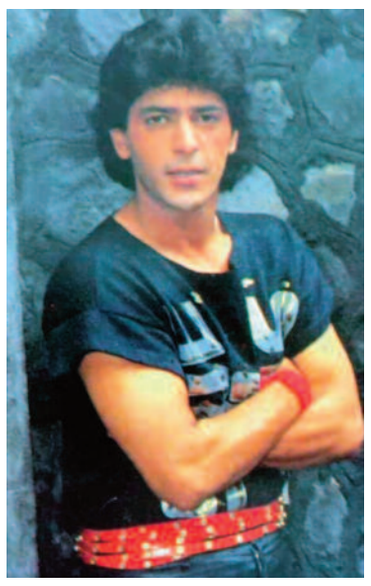

जब बॉलीवुड में फिल्में फ्लॉप हुईं, तो ये एक्टर भारत छोड़कर चला गया और पड़ोसी देश में इतना बड़ा स्टार बन गया कि उन्हें बांग्लादेश का अमिताभ बच्चन कहने लगे। बॉलीवुड में कई हीरो अपनी किस्मत आजमाते हैं, जिनमें से कुछ को सफलता हाथ लग जाती है और कुछ लंबे वक्त तक स्ट्रगल करते रहते हैं। इन्हीं में से एक स्टार थे जिन्हें बॉलीवुड में वो मुकाम हासिल नहीं हो पाया जो वो चाहते थे। इसीलिए उन्होंने पड़ोसी देश बांग्लादेश में अपना करियर बनाने की सोची और वहां वे इतने कामयाब हो गए कि लोग उन्हें बांग्लादेश का अमिताभ बच्चन कहने लगे।

बांग्लादेश का अमिताभ बच्चन

1990 के दशक के आखिर और 2000 के दशक में चंकी पांडे ने कई सफल बांग्लादेशी और भारत-बांग्लादेश जॉइंट वेंचर फिल्मों में लीड हीरो की भूमिका निभाई। बॉलीवुड में मुख्य अभिनेता के तौर पर उनका करियर धीमा पड़ने के बाद, उन्होंने सफलतापूर्वक बांग्लादेशी सिनेमा का रुख किया, जहां उनकी आवाज को बांग्ला में डब किया गया। चंकी की कुछ बांग्लादेशी फिल्मों में शामी केनो असामी (1997), मायराओ मानुष (1998), प्रेम कोरेची बेष कोरेची, फूल और पत्थर जैसी फिल्में शामिल हैं।

एक्टर का करियर

चंकी पांडे ने 1980 के दशक के आखिर में बॉलीवुड में डेब्यू किया और जल्द ही कमर्शियल सिनेमा में एक जाना-माना चेहरा बन गए। तेजाब जैसी फिल्मों में उनके अभिनय ने उन्हें दर्शकों के बीच पहचान दिलाने में मदद की। 1980 के दशक के आखिर और 1990 के दशक की शुरुआत में, चंकी कई सफल फिल्मों में नजर आए और बॉलीवुड के कई बड़े स्टार्स के साथ काम किया। उन्होंने कॉमेडी और एक्शन, दोनों तरह के रोल करने वाले एक लोकप्रिय एक्टर के तौर पर अपनी पहचान बनाई। 1980 के दशक के आखिर और 1990 के दशक की शुरुआत में,चंकी पांडे और नीलम बॉलीवुड की लोकप्रिय ऑन-स्क्रीन जोडियों में से एक थे। चंकी पांडे ने अपने दौर की कई मशहूर अभिनेत्रियों के साथ काम किया, जिनमें नीलम,माधुरी दीक्षित,मीनाक्षी शेषाद्रि और डिंपल कपाड़िया शामिल हैं।

भले ही उनका बॉलीवुड करियर धीमा पड़ गया था,लेकिन चंकी पड़ोसी देश में एक बड़े स्टार के तौर पर अपनी दूसरी पारी का आनंद ले रहे थे। उनका बांग्लादेश वाला दौर किसी भी बॉलीवुड एक्टर के करियर के सबसे अनोखे अध्यायों में से एक है। बांग्लादेश में कुछ साल काम करने के बाद,चंकी आखिरकार भारत लौट आए और हिंदी फिल्मों में फिर से एक्टिंग करने लगे। इस बार उन्होंने कैरेक्टर और कॉमिक रोल पर ज्यादा ध्यान दिया। फिल्मों से दूर,चंकी ने 1998 में भावना पांडे से शादी की। इस कपल की दो बेटियां हैं-अनन्या और राइसा; अनन्या बॉलीवुड में अपना करियर बना रही हैं।

नेगेटिव पीआर कंट्रोवर्सी पर शाहिद कपूर ने तोड़ी चुप्पी

फिल्म क्रिटिक अनुपमा चोपड़ा और अभिनेता शाहिद कपूर के बीच हुई एक बातचीत के दौरान आलिया भट्ट को लेकर दिए गए एक बयान ने सोशल मीडिया और मनोरंजन जगत में चर्चा तेज कर दी है। इस बातचीत में अनुपमा चोपड़ा ने दावा किया कि कान्स फिल्म फेस्टिवल के बाद आलिया भट्ट को जिस तरह की ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा, वह पूरी तरह से सामान्य नहीं थी, बल्कि इसके पीछे पेड नेगेटिव कैंपेन होने की आशंका जताई गई। अनुपमा चोपड़ा के इस बयान के अनुसार, आलिया भट्ट के खिलाफ की गई कुछ ऑनलाइन टिप्पणियां और सोशल मीडिया पर फैलाई गई नकारात्मक प्रतिक्रिया योजनाबद्ध तरीके से की गई प्रतीत होती हैं। उन्होंने यह भी इशारा किया कि इस पूरे मामले के पीछे किसी बड़े स्टार या प्रभावशाली व्यक्ति की भूमिका हो सकती है, हालांकि उन्होंने किसी का नाम स्पष्ट रूप से नहीं लिया। इस बातचीत के दौरान अभिनेता शाहिद कपूर भी मौजूद थे। अनुपमा चोपड़ा के इस दावे पर शाहिद कपूर ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर होने वाली ट्रोलिंग और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर चलने वाले कैंपेन आज के समय में एक गंभीर मुद्दा बन चुके हैं। हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर किसी आरोप की पुष्टि या खंडन नहीं किया, लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बिना ठोस सबूत के किसी पर आरोप लगाना सही नहीं होगा।

खेल समाचार

टीम इंडिया का मिशन वर्ल्ड कप 2027 शुरू

आज से भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का आगाज होने वाला है...रोहित शर्मा को इस श्रंखला में 2 बड़े चैलेंज का सामना करना पड़ा सकता है...

धर्मशाला,12 जून 2026। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैच की वनडे सीरीज शुरू होने वाली है। कल यानि 13 जून को धर्मशाला में पहला मुकाबला खेला जाने वाला है। भारतीय क्रिकेट के समर्थक रोहित शर्मा को एक्शन में देखने के लिए उत्सुक हैं। वर्ल्ड कप 2027 का सपना लिए रोहित चोट से वापसी कर रहे हैं। ऐसे में अफगानिस्तान वनडे सीरीज उनकी फॉर्म और फिटनेस का कड़ा इम्तेहान होने वाली है।

रोहित शर्मा की फिटनेस पर होगी नजरें

आईपीएल के दौरान मांसपेशियों में खिंचाव के कारण कुछ मैच नहीं खेल पाने वाले रोहित शर्मा अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की श्रृंखला के लिए समय रहते पूरी तरह से फिट हो गए हैं। आईपीएल 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ हिटमैन चोटिल हो गए थे। बीसीसीआई के सेंटर

ऑफ एक्सिलेंस में फिटनेस साबित करने के बाद वह एक्शन में नजर आने वाले हैं। भारत अक्टूबर-नवंबर 2027 में दक्षिण अफ्रीका में होने वाले विश्व कप की तैयारी कर रहा है। ऐसे में इस बात पर संदेह बना हुआ है कि क्या 39 वर्षीय रोहित वनडे विश्व कप तक टीम में बने रहेंगे या नहीं।

रोहित शर्मा का फॉर्म में लौटना जरूरी

वर्ल्ड कप 2027 की टीम में अपनी जगह पक्की करने के लिए रोहित शर्मा को लगातार अच्छा प्रदर्शन जारी रखना होगा। आईपीएल 2026 के साधारण प्रदर्शन के बाद टीम मैनेजमेंट उन्हें पैनी नजर से देखने वाला है। बता दें कि पिछले सीजन में रोहित ने 9 मैचों की इतनी ही पारियों में 283 रन बनाए थे। इस दौरान वह सिर्फ 2 बार पचास का आंकड़ा पार कर पाए थे।

विराट कोहली की गैरमौजूदगी से बढ़ी जिम्मेदारी

अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में भारतीय टीम और दर्शकों को विराट कोहली की कमी खलेगी जो मांसपेशियों में खिंचाव के कारण इस श्रृंखला से बाहर हो गए हैं। रोहित शर्मा पर भी विराट के बाहर होने का दबाव आ सकता है। गिल और रोहित के पारी की शुरुआत करने की उम्मीद है, जबकि कोहली की अनुपस्थिति में तीसरे नंबर पर ईशान किशन और यशस्वी जायसवाल में से किसी एक को उतारा जा सकता है। विश्व कप से पहले भारत को लगभग 25 वनडे मैच खेलने हैं, जिससे टीम को खिलाड़ियों और अलग-अलग संयोजन आजमाने का पर्याप्त मौका मिलेगा।

टीम इस प्रकार हैं...

भारतः-शुभमन गिल (कप्तान),यशस्वी जायसवाल,केएल राहुल,कुलदीप यादव, नितीश कुमार रेड्डी,प्रसिद्ध कृष्णा,श्रेयस अय्यर, रोहित शर्मा, हार्दिक पंड्या, वॉशिंगटन सुंदर, हर्ष दुबे, इशान किशन, अर्शदीप सिंह, गुरनूर बराड़, प्रिंस यादव।

अफगानिस्तान-: हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), सेदिकुल्लाह अटल,रहमानुल्लाह गुरबाज़ (विकेटकीपर),इकरामअलिखिल (विकेटकीपर),अजमतुल्लाह उमरजई, बिलाल सामी,नांगेयालिया खरोती, फरीद अहमद मलिक,एएम ग़ज़नफ़र, मोहम्मद नबी,राशिद खान,दरविश रसूली,इब्राहिम जादरान,जिया उर रहमान शरीफी।

अंडर-19 क्रिकेट टीम में अर्जुन का चयन

जालंधर,12 जून 2026। हिम्मत, हौसला और जुनून हो तो सपनों की उड़ान अमीरी-गरीबी कभी नहीं देखती। वह सिर्फ मेहनत और लगन का साथ देती है। जालंधर के राम नगर में छोले-कुलचे की छोटी-सी रेहड़ी लगाने वाले होती राम के बेटे अर्जुन राजपूत ने इस बात को जीवंत उदाहरण बनाकर साबित कर दिया है। अर्जुन का चयन भारतीय अंडर-19 क्रिकेट टीम में हो गया है। जब अगले महीने 4 जुलाई को टीम श्रीलंका दौरे पर रवाना होगी,जहां यह जालंधर का लड़का देश की नीली जर्सी पहनकर मैदान पर उतरेगा। परिवार ने उम्मीद जताई है कि घर का लाल,मैदान पर टीम इंडिया के लिए काफी रन के साथ विकेट भी चटकाएगा। अर्जुन लेफ्ट-हैंड बल्लेबाज और राइट-आर्म ऑफ स्पिनर है। अर्जुन ने क्रिकेट की शुरुआत हरभजन सिंह क्रिकेट अकादमी से की थी। सीमित संसाधनों के बीच उन्होंने कभी हार नहीं मानी। कोच विक्रम सिद्धू का पूरा साथ मिलता रहा, जिसने उनके हौसले को और मजबूत किया। टीम इंडिया में सिलेक्शन पाने के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान अर्जुन राजपूत ने कहा कि मैंने 8-9 साल की उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू किया था। इस मुकाम तक पहुंचकर बहुत खुशी हो रही है। श्रीलंका में हमारे शुरुआती मैच होंगे। हम देश का प्रतिनिधित्व करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि अच्छा प्रदर्शन करें, सारे मैच जीतें और ट्रॉफी भारत लाएं। मां-पिता और परिवार ने हमेशा मेरा साथ दिया।

पीवी सिंधु ने सेमीफाइनल में जगह पक्की की

सिडनी,12 जून 2026। दुनिया की 10 वें नंबर की खिलाड़ी पीवी सिंधु ने सिडनी के क्वेसेंटर में चल रहे ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। उन्होंने चीनी ताइपे की चेन सु यू को एकतरफा मुकाबले में हराया। सिर्फ 27 मिनट चले इस मैच में, तीसरी वरीयता प्राप्त भारतीय खिलाड़ी ने शुरुआत से ही दोनों गेम पर अपना दबदबा बनाए रखा और 21-6, 21-9 से जीत हासिल की। यह इस सीज़न में सिंधु का दूसरा सेमीफाइनल है; इससे पहले वह मलेशिया ओपन 2026 में भी अंतिम चार में पहुंची थीं। सिंधु के लिए एक दिलचस्प सेमीफाइनल का इंतज़ार है,क्योंकि दो बार की ओलंपिक पदक विजेता का मुकाबला शीर्ष वरीयता प्राप्त और तीन बार की विश्व चैंपियन अकाने यामागुची से होगा। यह दोनों के बीच 29वां मुकाबला होगा,जिसमें सिंधु का हेड-टू-हेड रिकॉर्ड 15-13 से उनके पक्ष में है। हालांकि,जापानी खिलाड़ी ने पिछले पांच मुकाबलों में से चार में जीत हासिल की है। यह नतीजा इस सीज़न के आठ बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर इवेंट्स में सिंधु का दूसरा सेमीफाइनल है,जिससे उन्हें सर्किट पर उतार-चढ़ाव भरे प्रदर्शन के बाद सही समय पर आत्मविश्वास मिला है।

केन विलियमसन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को कहा अलविदा

न्यूजीलैंड,12 जून 2026। न्यूजीलैंड क्रिकेट के दिग्गज बल्लेबाज और पूर्व कप्तान केन विलियमसन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। उनके इस फैसले के साथ क्रिकेट जगत में एक लंबे और सफल करियर का अंत हो गया है। विलियमसन ने 16 साल तक न्यूजीलैंड का प्रतिनिधित्व किया और इस दौरान वह टीम के सबसे भरोसेमंद और सफल बल्लेबाजों में शामिल रहे। उन्होंने 2010 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया था और इसके बाद लगातार टीम के लिए कई यादगार पारियां खेलीं। अपने करियर में उन्होंने कुल 378 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले और 19,346 रन बनाए,जो उन्हें न्यूजीलैंड क्रिकेट इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी बनाता है। उनके नाम 48 अंतरराष्ट्रीय शतक और छह दोहरे शतक भी दर्ज हैं, जो उनकी निरंतरता और तकनीकी मजबूती को दर्शाते हैं।

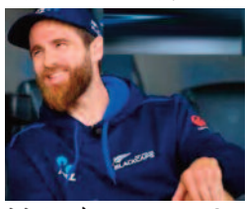

छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए बिछा रेड कारपेट

9,580 करोड़ रुपये के मिले प्रस्ताव...

- इन्वेस्टर कनेक्ट में हैदराबाद के निवेशकों को मुख्यमंत्री साय का निमंत्रण
- आईटी,टेक्सटाइल,डेटा सेंटर,फार्मा के क्षेत्र में खुली 7,800 रोजगार की राह

रायपुर,12 जून 2026। छत्तीसगढ़ ने निवेश आकर्षित करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। हैदराबाद में आयोजित 'छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट' कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों की सात प्रमुख कंपनियों ने 9,580 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव दिए हैं,जिनसे 7,800 से अधिक रोजगार सृजित होने की संभावना है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने देश के प्रमुख उद्योगपतियों और निवेशकों को छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए कहा विकसित भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में छत्तीसगढ़ तेजी से उभर रहा है और राज्य में निवेशकों के लिए'रेड कारपेट' बिछा हुआ है। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन सहित दक्षिण भारत के कई बड़े उद्योगपति, निवेशक और कारोबारी प्रतिनिधि मौजूद रहे।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री साय ने बताया कि नई औद्योगिक नीति लागू होने के बाद दिल्ली,मुंबई, बेंगलुरु के साथ-साथ जापान और दक्षिण कोरिया में आयोजित इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य को 8 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। राज्य सरकार इन प्रस्तावों को धरातल पर उतारने के लिए तेजी से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ आज निवेश के लिए देश के सबसे बेहतर राज्यों में से एक बनकर उभर रहा है। राज्य में उद्योगों के लिए आसान प्रक्रियाएं,सिंगल विंडो व्यवस्था,बेहतर बुनियादी सुविधाएं और उद्योग अनुकूल नीतियां उपलब्ध हैं। उन्होंने निवेशकों को छत्तीसगढ़ में उद्योग स्थापित करने का आमंत्रण दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हैदराबाद ने आईटी,फार्मा,बायो टेक्नोलॉजी और एयरोस्पेस जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। छत्तीसगढ़ भी इन क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहा है और दोनों राज्यों के उद्योगपति एवं उद्यमी मिलकर नए अवसरों का लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने कहा कि मध्य भारत में स्थित छत्तीसगढ़ देश का सबसे उपयुक्त लॉजिस्टिक हब बनने की क्षमता रखता है। छत्तीसगढ़ सात राज्यों से घिरा हुआ है और 60 करोड़ से अधिक उपभोक्ताओं तक सीधी पहुंच प्रदान करता है। रेलवे नेटवर्क, भारतमाला परियोजना, एयर कार्गो सुविधाओं तथा खनिज संसाधनों की उपलब्धता उद्योगों के लिए इसे अत्यंत अनुकूल बनाती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ देश में ग्रीन स्टील को बढ़ावा देने वाले अग्रणी राज्यों में शामिल है। ऊर्जा क्षेत्र में राज्य को 3.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिससे प्रदेश देश के प्रमुख पावर हब के रूप में उभर रहा है। उन्होंने सात प्रमुख कंपनियों को छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए 'इन्विटेशन टू इन्वेस्ट' (ऑफर लेटर) प्रदान किए। इनमें डेटा सेंटर, सीमेंट,सेमीकंडक्टर एवं जीपीयू इंफ्रास्ट्रक्चर,सौर ऊर्जा उपकरण निर्माण,वस्त्र,फार्मास्यूटिकल और डेयरी प्रसंस्करण क्षेत्रों की अग्रणी कंपनियां शामिल हैं। सबसे बड़ा निवेश प्रस्ताव हाइपरनेक्स्ट डाटा सेंटर लिमिटेड की ओर से प्राप्त हुआ, जिसने छत्तीसगढ़ में भारत का पहला समर्पित डिजास्टर रिकवरी डेटा सेंटर कैंपस स्थापित करने के लिए 4,200 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव दिया। इस परियोजना से राज्य में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती मिलेगी और छत्तीसगढ़ डेटा सेंटर क्षेत्र का महत्वपूर्ण केंद्र बन सकेगा। इस परियोजना से लगभग 250 रोजगार सृजित होंगे। फीग्रेड एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ने सीमेंट क्षेत्र में 2,912 करोड़ रुपये निवेश का प्रस्ताव दिया है, जिससे लगभग 4,000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है।

वहीं निवाई लैब्स प्राइवेट लिमिटेड ने 1,000 करोड़ के निवेश से एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस), जीपीयू इंफ्रास्ट्रक्चर, एडवांस कंप्यूटिंग और सेमीकंडक्टर असेंबली से जुड़ी सुविधाएं विकसित करने का प्रस्ताव दिया। इससे राज्य में आधुनिक तकनीकी उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा एवं लगभग 200 रोजगार सृजित होंगे। सौर ऊर्जा उपकरण निर्माण क्षेत्र की एसजी मार्ट लिमिटेड ने 700 करोड़ रुपये निवेश का प्रस्ताव दिया है,जिससे लगभग 450 लोगों को रोजगार मिल सकता है। सरवणा मिल्स प्राइवेट लिमिटेड ने 528 करोड़ के निवेश से अत्याधुनिक टेक्सटाइल और परिधान निर्माण इकाई स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। इस परियोजना से लगभग 2,500 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। फार्मास्यूटिकल क्षेत्र की काबरा ड्रग्स ने 200 करोड़ रुपये तथा डेयरी क्षेत्र की दिनशॉज़ डेयरी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड ने 40 करोड़ रुपये निवेश का प्रस्ताव दिया है। इन दोनों परियोजनाओं से क्रमशः लगभग 250 और 150 रोजगार सृजित होंगे।

छत्तीसगढ़ में बदला स्कूलों का समय

16 जून से नए शेड्यूल पर खुलेंगे स्कूल

रायपुर,12 जून 2026। छत्तीसगढ़ के स्कूली छात्र-छात्राओं और शिक्षकों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण प्रशासनिक खबर सामने आई है। राज्य में भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप के बीच बिताई गई लंबी छुट्टियों के बाद अब सभी स्कूल आगामी 16 जून से पूरी तरह खुलने जा रहे हैं। लोक शिक्षण संचालनालय ने शुक्रवार को इस संबंध में एक आधिकारिक और विस्तृत आदेश जारी कर दिया है। इस नए सरकारी आदेश के तहत प्रदेश के सभी संभागीय संयुक्त संचालकों और जिला शिक्षा अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने अधिकार क्षेत्रों में 16 जून 2026 से सभी प्राथमिक,माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का नियमित संचालन सुनिश्चित करें। इस फैसले के दायरे में राज्य के सभी सरकारी स्कूल और निजी (अशासकीय) शैक्षणिक संस्थान समान रूप से शामिल होंगे, जिन्हें इस नियमावली का सख्ती से पालन करना होगा।

शैक्षणिक सत्र 2026-27 का नियमित संचालन 16 जून से होगा शुरू : स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए आधिकारिक दिशा-निर्देशों के अनुसार, छत्तीसगढ़ राज्य के सभी स्कूलों में इस वर्ष 20 अप्रैल 2026 से लेकर 15 जून 2026 तक के लिए कुल 57 दिनों के ग्रीष्मकालीन अवकाश की घोषणा की गई थी। अब इस घोषित अवकाश की अवधि समाप्त होने के तुरंत बाद, नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 का नियमित और सुचारू संचालन 16 जून, दिन मंगलवार से शुरू कर दिया जाएगा। सरकार के इस कदम का मुख्य उद्देश्य नए सत्र की पढ़ाई को समय पर शुरू करना है ताकि बच्चों के पाठ्यक्रम को बिना किसी देरी के पूरा किया जा सके। लोक शिक्षण संचालनालय ने स्पष्ट किया है कि पहले दिन से ही स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति और शिक्षकों की पाबंदी को अनिवार्य रूप से लागू किया जाएगा ताकि शिक्षण व्यवस्था में कोई व्यवधान न आए।

भीषण गर्मी को देखते हुए प्राचार्यों और जिला शिक्षा अधिकारियों को मिले निर्देश : नए सत्र की शुरुआत के साथ ही शिक्षा विभाग ने राज्य में मौसम के मिजाज और बढ़ती गर्मी को लेकर भी गहरी चिंता व्यक्त की है। यद्यपि स्कूल खोलने की तारीख 16 जून तय की गई है,लेकिन लोक शिक्षण संचालनालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और स्कूल प्राचार्यों को जमीनी स्तर पर विशेष एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। आदेश में कहा गया है कि स्कूल परिसरों में बच्चों के लिए शुद्ध और ठंडे पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। इसके साथ ही,भीषण गर्मी और लू के प्रकोप से मासूम बच्चों को बचाने के लिए प्राथमिक चिकित्सा और ओआरएस के पैकेट जैसी आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं हर समय स्कूल में उपलब्ध रहनी चाहिए।

सरकारी और निजी स्कूलों को करना होगा नियमों का अनिवार्य रूप से पालन : लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी यह नया आदेश पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में समान रूप से प्रभावी होगा। सरकार ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि चाहे सरकारी स्कूल हों, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल हों या फिर बड़े निजी स्कूल (प्राइवेट स्कूल),सभी को 16 जून 2026 से ही अपने संस्थानों को नियमित रूप से खोलना होगा। कोई भी निजी स्कूल अपनी मनमर्जी से छुट्टियों की अवधि को आगे नहीं बढ़ा सकेगा और न ही तय तारीख से पहले या बाद में कक्षाएं संचालित करने का मनमाना फैसला ले सकेगा। यदि कोई भी शिक्षण संस्थान इस सरकारी गाइडलाइन का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है या तय समय सीमा के भीतर स्कूल खोलने में कोताही बरतता है, तो संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा उस संस्थान के खिलाफ कानूनी और दंडात्मक कूटनीतिक कार्रवाई की जाएगी।

परिवहन विभाग ने घेरीं 350 बसें,स्लीपर बसों से हटे अवैध स्लाइडर,5.50 लाख का जुर्माना

रायपुर,12 जून 2026। छत्तीसगढ़ की सड़कों पर सफर करने वाले यात्रियों की सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग अचानक फुल एक्शन मोड में आ गया है। सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सख्ती के बाद पूरे प्रदेश में बसों की ताबड़तोड़ चेकिंग शुरू हो गई है। आरटीओ की टीमों ने हाईवे से लेकर बस स्टैंडों तक घेराबंदी करके करीब 350 बसों को चेक किया है। इस दौरान नियमों की धज्जियां उड़ाने वाली बसों पर कार्रवाई करते हुए अधिकारियों ने मौके पर ही 5.50 लाख रुपए का जुर्माना ठोक दिया।

रायपुर-बिलासपुर रूट की स्लीपर बसों में हड़कंप,तोड़े गए अवैध केबिन : परिवहन आयुक्त एस. प्रकाश के निर्देश पर इस बार सबसे बड़ी गाज स्लीपर कोच बसों पर गिरी है। अक्सर बस मालिक कमाई के चक्कर में बसों के भीतर एक्स्ट्रा केबिन और स्लीपर बर्थ में अवैध स्लाइडर लगा लेते हैं, जिससे हादसे के वक्त यात्रियों का निकलना मुश्किल हो जाता है। चेकिंग के दौरान रायपुर,बिलासपुर और दुर्ग जैसे बड़े शहरों के रूट पर चलने वाली बसों में ऐसे जितने भी अवैध पार्टीशन मिले,उन्हें आरटीओ की टीम ने मौके पर ही हथौड़े मारकर तोड़ दिया।

बसों में आग बुझाने के इंतजाम नहीं, जीपीएस भी मिला बंद : जांच में कई चौंकाने वाली कमियां भी सामने आई हैं। कई बसों में आग बुझाने के लिए जरूरी 10 किलो का अग्निशमन यंत्र (फायर एक्स्टिंग्विशर) गायब था या फिर एक्सपायर हो चुका था। इसके अलावा,यात्रियों की लोकेशन ट्रेस करने वाला जीपीएस सिस्टम भी बंद मिला। अफसरों ने साफ कह दिया है कि बिना परमिट,बिना फिटनेस और तय मानकों के बिना सड़क पर दौड़ने वाली बसों को सीधे जब्त किया जाएगा।

कमिश्नर की सख्त चेतावनी-अब सीधे रद्द होगा परमिट : परिवहन आयुक्त ने राज्य के सभी आरटीओ और जिला परिवहन अधिकारियों को फील्ड पर डटे रहने को कहा है। उन्होंने साफ लहजे में हिदायत दी है कि यात्रियों की जान से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। जो भी बस संचालक लापरवाही करेगा, उसका चालान काटने के साथ-साथ परमिट और ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड करने की कार्रवाई की जा रही है।

स्ट्रीट वेंडर्स के सपनों को मिली नई उड़ान....छत्तीसगढ़ में 1.12 लाख से अधिक वेंडर्स को मिला आर्थिक संबल

रायपुर,12 जून 2026। कभी सड़क किनारे ठेला लगाकर सब्जियां बेचने वाले, चाय-नाश्ते की छोटी दुकान चलाने वाले या फिर फुटपाथ पर रोजी-रोटी कमाने वाले लाखों स्ट्रीट वेंडर (रेहड़ी-पटरी व्यवसायियों) के लिए पूंजी की कमी सबसे बड़ी चुनौती थी। बैंक ऋण तक पहुंच नहीं होने के कारण उनका व्यवसाय सीमित था। लेकिन प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना ने इन छोटे उद्यमियों के जीवन में बदलाव की नई कहानी लिखी है। छत्तीसगढ़ में इस योजना के माध्यम से अब तक 1 लाख 12 हजार 36 से अधिक स्ट्रीट वेंडर (पथ विक्रेताओं) को 256 करोड़ 94 लाख रुपये से अधिक की ऋण सहायता उपलब्ध कराई जा चुकी है। योजना ने न केवल उनके कारोबार को मजबूती दी है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भरता और सम्मानजनक आजीविका का नया अवसर भी प्रदान किया है। कोविड-19 महामारी के दौरान आजीविका पर पड़े गंभीर प्रभाव को देखते हुए केंद्र सरकार ने 1 जून 2020 को प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना शुरू की थी। इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों

में काम करने वाले स्ट्रीट वेंडर को बिना गारंटी कार्यशील पूंजी ऋण उपलब्ध कराना है, ताकि वे अपने व्यवसाय को फिर से शुरू कर सकें और उसका विस्तार कर सकें। योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें किसी प्रकार की गारंटी की आवश्यकता नहीं होती। समय पर ऋण चुकाने वाले हितग्राहियों को अगले चरण में अधिक राशि का ऋण प्राप्त करने का अवसर मिलता है। योजना के तहत लाभार्थियों को चरणबद्ध तरीके से ऋण उपलब्ध कराया जाता है। प्रथम चरण में 10,000 रूपए तक का ऋण, द्वितीय चरण में 20,000 रूपए तक का ऋण तथा तृतीय चरण में 50,000 रूपए तक का ऋण दिया जाता है। अर्थात इस योजना के अंतर्गत न्यूनतम 10 हजार रुपये से लेकर अधिकतम 50 हजार रुपये तक की कार्यशील पूंजी ऋण सहायता प्राप्त की जा सकती है। समय पर पुनर्भुगतान करने वाले हितग्राही ही अगले चरण के लिए पात्र बनते हैं। पीएम स्वनिधि योजना का लाभ उन छोटे कारोबारियों को मिलता है जो सड़क किनारे या सार्वजनिक स्थानों पर वस्तुएं एवं सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। इनमें सब्जी एवं फल विक्रेता, चाय,नाश्ता एवं फास्ट फूड विक्रेता, पान दुकान संचालक,कपड़ा एवं रेडीमेड वस्त्र विक्रेता,जूता-चप्पल विक्रेता,किताब एवं स्टेशनरी विक्रेता,फूल एवं पूजा सामग्री विक्रेता, मोबाइल एक्सेसरीज विक्रेता,नाई, मोची,लॉन्ड्री जैसी सेवाएं देने वाले स्वरोजगारी,जैसे अनेक छोटे व्यवसाय शामिल हैं। छत्तीसगढ़ में योजना का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। दुर्ग, रायपुर,बिलासपुर, कोरबा,रायगढ़ और धमतरी जैसे जिलों में हजारों पथ विक्रेताओं को ऋण सहायता प्रदान की गई है। राज्य स्तर पर 267.22 करोड़ रुपये की स्वीकृत राशि के विरुद्ध 256.94 करोड़ रुपये से अधिक का वितरण किया जा चुका है,जिससे 1.12 लाख से अधिक हितग्राही लाभान्वित हुए हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का कहना है कि पीएम स्वनिधि योजना केवल ऋण वितरण कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह छोटे उद्यमियों को औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने का एक व्यापक अभियान है। इससे स्ट्रीट वेंडर्स की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है,उनकी आय में वृद्धि हो रही है और वे अपने परिवार के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण कर पा रहे हैं।

पीएम आवास के बहाने डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा...'पिछली सरकार में लाखों परिवार पक्के मकान से वंचित रहे...'

रायपुर,12 जून 2026। डिप्टी सीएम एवं पंचायत-ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा ने सीएम विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में राज्य की प्रगति की जानकारी दी। साथ ही पिछली कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा।

पत्र में क्या लिखा विजय शर्मा ने...?

विजय शर्मा ने लिखा है कि पिछले ढाई साल में सभी के सहयोग से योजना में उल्लेखनीय उपलब्धियां मिली हैं। कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि पीएम आवास ग्रामीण के लिए जरूरी आवंटन न होने से लाखों गरीब परिवार पक्के आवास से वंचित रह गए। उन्होंने पूर्व पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव के इस्तीफे का जिक्र करते हुए कहा कि उस वक्त गरीबों के आवास के लिए पर्याप्त राशि नहीं दी जा सकी थी।

'मोर आवास-मोर अधिकार' का जिक्र

पत्र में बताया कि भाजपा ने विपक्ष में रहते हुए 'मोर आवास-मोर अधिकार' आंदोलन चलाया और गरीबों को पक्का मकान देने का संकल्प लिया। सरकार बनने के बाद 14 दिसंबर को पहली कैबिनेट में 18,12,742 आवास पूरे करने का फैसला हुआ। इसमें अधूरे आवास, प्रतीक्षा सूची,आवास प्लस सूची और मुख्यमंत्री आवास योजना के मकान शामिल हैं।

कुल कितने आवास बन रहे...

1. पीएम जनमन योजनाः 33,601 आवास।
2. नक्सल प्रभावित क्षेत्रः विशेष प्रोजेक्ट के तहत 15 हजार अतिरिक्त आवास।
3. कुल लागतः पिछले ढाई साल में 26,908 करोड़ रुपए खर्च कर 10.60 लाख से ज्यादा आवास पूरे।
4. 2025-26 का टारगेटः 6 लाख से ज्यादा आवास पूरे होने का दावा,

कांकेर में आसमानी आफत : अंतागढ़ के कलगांव में आकाशीय बिजली गिरने से उप-सरपंच समेत 3 की मौत,5 जने झुलसे

कांकेर,12 जून 2026। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले से एक बेहद दर्दनाक और झकझोर देने वाली खबर सामने आई है। छत्तीसगढ़ के कांकेर के अंतागढ़ में मनरेगा कार्य के दौरान पेड़ के नीचे खड़े ग्रामीणों पर बिजली गिरने से उप सरपंच समेत 3 लोगों की मौत हो गई।जबकि पांच लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। इस अचानक हुए हादसे के बाद प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया और अधिकारी तुरंत मौके पर रवाना हुए।

बारिश से बचने पेड़ के नीचे खड़े थे मजदूर : मिली जानकारी के अनुसार,कलगांव में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत तालाब निर्माण का कार्य चल रहा था,जिसमें गांव के करीब 50 मजदूर काम पर लगे हुए थे। इसी दौरान सुबह-सुबह अचानक मौसम का मिजाज बदला और तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश शुरू हो गई। पानी से खुद को बचाने के लिए कई मजदूर पास ही स्थित एक पेड़ के नीचे जाकर खड़े हो गए। इसी बीच कड़कड़ाती हुई आकाशीय बिजली सीधे उसी पेड़ पर जा गिरी। इस दर्दनाक हादसे में पेड़ के नीचे खड़े कलगांव के उपसरपंच धनराज पटेल और उनके साथ काम कर रहे एक अन्य मजदूर की मौके पर ही तड़प-तड़प कर मौत हो गई। वहीं,आकाशीय बिजली की चपेट में आने से पांच अन्य मजदूर झुलस गए,जिनमें 3 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल हैं। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और आसपास काम कर रहे अन्य मजदूर तुरंत मदद के लिए दौड़े। सभी घायल मजदूरों को आनन-फानन में उपचार के लिए अंतागढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों की टीम उनकी निगरानी कर रही है। घटना की गंभीरता को देखते हुए कांकेर कलेक्टर निलेश महादेव क्षीरसागर ने बताया कि प्रशासनिक अधिकारियों को तुरंत मौके पर और अस्पताल भेजा गया है। कलेक्टर ने कहा,'मौके पर पहुंचे अधिकारी स्थिति का पूरा जायजा ले रहे हैं। घायलों को त्वरित राहत देने के लिए एंबुलेंस रवाना की गई थी। इसके साथ ही डॉक्टरों को सख्त और आवश्यक निर्देश दिए गए हैं कि सभी घायल ग्रामीणों का बेहतर से बेहतर इलाज सुनिश्चित किया जाए।

कांग्रेस की आदिवासी नेताओं की बैठक में 12 सूत्रीय राजनीतिक प्रस्ताव पारित

जल-जंगल-जमीन से लेकर आरक्षण और पेसा कानून तक उठी मांग

रायपुर,12 जून 2026। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से आयोजित आदिवासी नेताओं की महत्वपूर्ण बैठक में आदिवासी समाज से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। बैठक में जल,जंगल,जमीन,वन अधिकार, पेसा कानून,आरक्षण,विस्थापन, रोजगार और समान नागरिक संहिता (यूसीसी) जैसे विषयों पर मंथन करते हुए 12 सूत्रीय राजनीतिक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत,पूर्व उपमुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव और पूर्व मंत्री ताम्रध्वज साहू सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया। बैठक में आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और आदिवासी अधिकारों की रक्षा के लिए रणनीति बनाने पर भी चर्चा की गई।

पारित प्रस्ताव में हसदेव अरण्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में प्रस्तावित खनन परियोजनाओं और वन भूमि डायवर्जन की अनुमति रद्द करने,जनसंख्या के अनुपात में 32 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति आरक्षण लागू करने,वनाधिकार पट्टों का वितरण, पेसा कानून और संविधान की पांचवीं अनुसूची के प्रभावी क्रियान्वयन,नक्सल प्रभावित निर्दोष आदिवासियों की रिहाई,स्थानीय रोजगार में प्राथमिकता तथा ग्राम सभाओं के अधिकारों की रक्षा जैसी मांगें प्रमुख रूप से शामिल हैं।

बैठक में समान नागरिक संहिता के दायरे से आदिवासी समाज को बाहर रखने, आदिवासियों की विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान बनाए रखने,'वनवासी' शब्द के प्रयोग का विरोध करने तथा आगामी जनगणना में आदिवासियों के लिए अलग पहचान संबंधी प्रावधान किए जाने की भी मांग उठाई गई। इस अवसर पर कांग्रेस के कई विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, आदिवासी कांग्रेस के पदाधिकारी और विभिन्न जिलों के वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे।

'पुलिस प्राइवेट वसूली एजेंट नहीं': हाईकोर्ट की फटकार एनबीएफसी के 53 करोड़ होल्ड करने का आदेश रद्द

बिलासपुर,12 जून 2026। डिवीजन बेंच ने साफ कहा कि पुलिस किसी कमर्शियल विवाद में निजी रिकवरी एजेंट की तरह काम नहीं कर सकती। ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सख्त रुख अपनाया है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने साफ कहा कि पुलिस किसी कमर्शियल विवाद में निजी रिकवरी एजेंट की तरह काम नहीं कर सकती। कोर्ट ने एक एनबीएफसी कंपनी के बैंक खाते से 53.47 करोड़ रुपए होल्ड करने के पुलिस आदेश को रद्द कर दिया। नई दिल्ली की 'ऑक्सीजो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड' उद्योगों और छोटे कारोबारियों को लोन देती है।

कंपनी का खाता कोटक महिंद्रा बैंक, रायपुर में है। इसमें देशभर के कर्जदारों से ईएमआई के रूप में रोज 12-15 करोड़ रुपए आते हैं। कंपनी ने रायपुर की फर्म 'श्रीजीकृपा प्रोजेक्ट लिमिटेड' को कच्चा माल खरीदने के लिए करीब 10 करोड़ की लोन सुविधा दी थी। बाद में श्रीजीकृपा और उसकी सप्लायर कंपनी 'ओएफबी टेक' के बीच वजन में गड़बड़ी को लेकर विवाद हुआ। इस पर मंदिर हसौद थाने में पहले 6.9 लाख और बाद में 43.38 लाख रुपए की धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज हुई। जांच के दौरान मंदिर हसौद पुलिस ने बिना ठोस कानूनी आधार के ऑक्सीजो फाइनेंस के पूरे खाते पर रोक लगा दी। कंपनी के 53,47,17,835 रुपए होल्ड कर दिए। विवाद बढ़ने पर पुलिस ने नया आदेश जारी कर राशि घटाकर 43.38 लाख रुपए होल्ड रखी। ऑक्सीजो फाइनेंशियल ने याचिका में कहा कि वह न तो एफआईआर में आरोपी है, न ही शॉर्ट-सप्लाई या धोखाधड़ी से उसका कोई सीधा लेना-देना।

प्रकाशक,मुद्रक,स्वामी अविनाश कुमार सिंह के द्वारा साईं ऑफ्सेट प्रिंटर्स,नमनाकला,संत हरकेवल विद्यापीठ के पास,अम्बिकापुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-अविनाश कुमार सिंह* (पी.आर.बी.कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिए जिम्मेदार)
RNI Reg.No.CHHHIN/2004/15050,डॉक रजिस्टर्ड क्र.:-13/सरगुजा/डीएन/2026-2028-मो. 94062-23001,98265-32611,Email:ghatatighatana11@ gmail.com,Website:www.ghatatighatana.com, (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र अम्बिकापुर न्यायालय मान्य होगा)